

संस्करण : मुंबई

वर्ष : 10

अंक : 271

पृष्ठ : 8

मूल्य : 2.00

मंगलवार, 07 अक्टूबर, 2025

जुनून है सच लिखने का

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित



3 स्वामीनाथन और टाटा फाउंडेशन के साथ...

4 जनता को किया वोटिंग से किनारा, विपक्ष ने ...

7 प्रमोद भगत ने अपना स्वर्णिम अभियान ...

संक्षिप्त न्यूज

तमिलनाडु की पहचान पर हमला

स्टालिन बोले- हिंदी थोपने और आरएसएस की मनुस्मृति सोच के खिलाफ हैं ये लड़ाई

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को राज्यपाल आरएन रवि पर पलटवार करते हुए उन कई लड़ाइयों का जिक्र किया जो राज्य लड़ रहा है, संघीय अधिकारों की रक्षा से लेकर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा तक। राज्यपाल रवि ने पहले टिप्पणी की थी कि उन्होंने राज्य भर की दीवारों पर 'तमिलनाडु पोरादुम' (तमिलनाडु लड़ेगा) जैसे नारे लिखे



देखे थे और सवाल किया था। किससे लड़ें? कोई भी तमिलनाडु के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। राज्यपाल की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कि तमिलनाडु किसके खिलाफ लड़ रहा है? स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य अहंकार, कट्टरता और षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ता है जो शिक्षा, समानता और लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। स्टालिन ने एक विस्तृत बयान में कहा कि यह उन अहंकार के खिलाफ है जो कहता है कि शिक्षा के लिए धन तभी दिया जाएगा जब हिंदी को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने केंद्र पर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले संस्थानों में हिंदी थोपने और अंधविश्वास फैलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को दबाने वाली लोकतंत्र-विरोधी ताकतों और संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों से लड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने राज्यपाल के अधिकारों के अतिक्रमण के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बार-बार अदालतों का दरवाजा खटखटाया है।

सनातन का अपमान नहीं सहेंगे कहते हुए वकील ने CJI गर्वाई पर की जूता फेंकने की कोशिश, आरोपी हिरासत में लिया गया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गर्वाई पर हमला करने की कोशिश की। यह घटना तब घटी जब सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ वकीलों द्वारा मामलों की सुनवाई कर रही थी। सूत्रों के अनुसार, वकील मंच के पास गया और अपना जूता निकालकर जज पर फेंकने की कोशिश की। हालांकि, अदालत में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और वकील को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते समय वकील को यह कहते सुना गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा इस सब से विचलित न हों। हम विचलित नहीं हैं। ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करती। यह घटना संभवतः खजुराहो में भगवान विष्णु की सात फुट



न्यायाधीश गर्वाई की टिप्पणियों से प्रेरित थी। उस मामले को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था जाओ और देवता से ही कुछ करने को कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो। तो अभी जाकर प्रार्थना करो। यह एक पुरातात्विक स्थल है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसएसआई) को अनुमति वगैरह देनी होगी। इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था और कई लोगों ने मुख्य न्यायाधीश पर धार्मिक भावनाओं

को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। दो दिन बाद खुली अदालत में इस विवाद पर बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश गर्वाई ने कहा कि उनका कोई अनादर करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ... यह सब

सोशल मीडिया पर हुआ।' केंद्र सरकार की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश का समर्थन करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर अक्सर घटनाओं पर प्रतिक्रियाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।

बीसीआई ने वकील राकेश किशोर को किया निलंबित, सीजेआई पर जूता उछालने की कोशिश की थी

नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने वकील राकेश किशोर के अदालतों में प्रेक्टिस करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राकेश किशोर ने सोमवार को कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति बीआर गर्वाई पर जूता उछालने की कोशिश की थी। वकीलों के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई, जब सीजेआई गर्वाई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ किसी मामले में सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील राकेश किशोर ने सीजेआई गर्वाई पर जूता उछालने की कोशिश की। हालांकि, यह जूता उन तक नहीं पहुंचा। वकील ने जब डाइस की ओर बढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए और उन्हें कोर्ट रूम से बाहर ले गए। जब वकील को ले जाया जा रहा था तो उन्हें यह कहते सुना गया- सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। वह कथित तौर पर भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना पर पिछले दिनों सीजेआई की टिप्पणी से नाखुश थे। घटना के दौरान संयम बनाए रखा और कोर्ट रूम को कहा, इस सबसे विचलित मत होइए। हम विचलित नहीं होते। ये बातें मुझ पर असर नहीं करती।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया अध्याय! राजनाथ सिंह करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर' पर एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित यह सम्मेलन, रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ क्षेत्रीय औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास को संरक्षित करने के उद्देश्य से, MoD और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए एक केंद्रित मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान, रक्षा मंत्री नए डिफेंस एक्जिज्युटिव पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जिसे नियमित और आयात प्राधिकरण जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही, श्रीजन डीईईपी (रक्षा

प्रतिष्ठान और उद्यमी मंच) पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जो भारतीय रक्षा उद्योगों की क्षमताओं और उत्पादों का मानचित्रण करने वाला एक डिजिटल संग्रह है। इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा और केंद्र शासित प्रदेशों का एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र नीति संग्रह और iDEX कॉफी टेबल बुक 'नवाचार के साझा क्षितिज' का भी विमोचन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उद्योग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाकर भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करना है। यह सम्मेलन स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने, रक्षा निर्यात बढ़ाने और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही, श्रीजन डीईईपी (रक्षा

न्यायपालिका के सम्मान पर हमला! सोनिया गांधी ने CJI पर जूता फेंकने की घटना को बताया संविधान पर आघात

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना की निंदा की है, जिसमें एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गर्वाई पर जूता फेंककर हमला करने की कोशिश की। सोनिया गांधी के बयान में कहा गया भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर सर्वोच्च न्यायालय में हुए हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। यह न केवल उन पर, बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। मुख्य न्यायाधीश गर्वाई बहुत दयालु रहे हैं, लेकिन पूरे देश को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। यह चौंकाने वाला बयान 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर द्वारा कथित तौर पर अदालती कार्यवाही

के दौरान मुख्य न्यायाधीश गर्वाई पर जूता फेंकने के बाद आया है, लेकिन न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले किशोर को आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तक देश भर की किसी भी उा दालता, न्यायाधिकरण या कानूनी प्राधिकरण में कालत करने से रोक दिया गया है।



भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गर्वाई पर हमले की कोशिश के बाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता राकेश किशोर का लाइसेंस तत्काल

प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अदालती कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले किशोर को आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तक देश भर की किसी भी उा दालता, न्यायाधिकरण या कानूनी प्राधिकरण में कालत करने से रोक दिया गया है। एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें अधिवक्ता को आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि निलंबन जारी क्यों

नहीं रखा जाना चाहिए और आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली बार काउंसिल को बिना किसी ढेरी के आदेश लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसमें वकील की स्थिति को अपनी आधिकारिक सूची में अपडेट करना और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों को निलंबन के बारे में सूचित करना शामिल है। इससे पहले, दिन में सुप्रीम कोर्ट में उस समय कोर्टरूम ड्रामा शुरू हो गया जब एक वकील ने सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की। राकेश किशोर को कोर्टरूम से बाहर ले जाने समय उन्होंने चिल्लाकर कहा कि भारत सनातन धर्म का अपमान बढ़ाईत नहीं करेगा।

तेजस्वी का नीतीश पर तीखा हमला:

होश में नहीं हैं मुख्यमंत्री, बिहार को दहाड़ने वाला सीएम चाहिए

पटना। चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और इस महत्वपूर्ण चुनावी मुकामले के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार चुनाव की तारीखों पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर की तारीख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इस बार महागठबंधन की सरकार चाहिए। 20 साल तक उन्होंने राज्य को अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, अत्याचार और घोटाला दिया। बिहार की जनता अब इससे तंग आ चुकी है। सीएम



होगा जिसमें बेरोजगार युवा न हों। तेजस्वी आएंगे, तो सबको नौकरी देंगे। बिहार से बेरोजगारी जड़ से खत्म हो जाएगी। आज से एक उत्सव शुरू हो रहा है... तेजस्वी के साथ, इस बार

हर बिहारी सीएम होगा, वो सीएम होगा - चेंज मेकर। सीएम नीतीश पर वार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वह अपने होश में नहीं हैं। वह अब बिहार पर शासन करने के लायक नहीं हैं। तेजस्वी जो कहते हैं, यह निक्कामी, नकलची सरकार' वही करती है। उन्होंने अपना विजन नहीं बताया है...महागठबंधन इस बार सरकार बनाएगा और हर बिहारी सीएम होगा - चेंज मेकर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की आज की आधिकारिक घोषणा के बाद, बिहार चुनाव आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है... हमें चुनाव आयोग के रूप में एक रेफरी की जरूरत है, जो किसी भी पार्टी का पक्ष न ले।

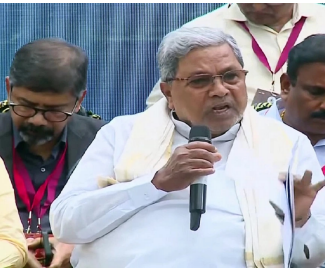
दिवाली पर हरित पटाखों पर प्रतिबंध हटाने के लिए दिल्ली सरकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली पर हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा पर शासन करने के लायक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रमाणित हरित पटाखों के उपयोग, जनभागीदारी सुनिश्चित करने और नियमों का पालन पर शासन करने के लिए निर्देश मांगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और उनकी सरकार ने शहर में करोड़ों लोगों द्वारा इस त्योहार को मनाने के मद्देनजर अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

अलग लिंगायत धर्म की मांग पर सिद्धारमैया ने कहा- लोगों का रुख ही मेरा रुख है

बैंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लिंगायतों को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लिंगायतों को एक अलग धर्म मानने की मांग एक पूर्व-भूमि का मामला है। न पूर्व-भूमि का, न ही पृष्ठभूमि का। कुछ क्रांतियुग स्वामीजी इस बारे में बात करते हैं। जब मंत्री शिवराज थंगाडगी ने उन्हें बताया कि पत्रकार इस मुद्दे पर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तीखी प्रतिक्रिया दी, 'हाँ! इस पर मेरा कोई रुख नहीं है। जनता का रुख ही मेरा रुख है। थंगाडगी ने सहमति जताते हुए कहा कि सरकार जनता के नज़रिए से सहमत है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई क्रांति या प्रांती नहीं होगी।

लिंगायत समुदाय ने अपने कई संतों के नेतृत्व में, रविवार को लिंगायत मातादीशारा ओक्कुटा द्वारा आयोजित 'बसव संस्कृति अभियान-2025' के समापन समारोह में एक अलग धर्म



के रूप में मान्यता की अपनी माँग दोहराई। पारित किए गए पाँच प्रस्तावों में लिंगायतों के लिए धार्मिक मान्यता के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल था। 2018 में तत्कालीन

सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लिंगायतों को 'धार्मिक अल्पसंख्यक' का दर्जा देने की सिफारिश करने के कदम ने कथित तौर पर लिंगायत-बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी हार में योगदान दिया। समुदाय खुद भी विभाजित है: एक समूह का तर्क है कि लिंगायत और वीरशैव एक ही हैं, जबकि दूसरा समूह लिंगायतों के लिए अलग मान्यता चाहता है और वीरशैव को हिंदू धर्म के सात शैव संप्रदायों में से एक मानता है। यह विभाजन रविवार को स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जब भाजपा से जुड़े नेताओं और अखिल भारत वीरशैव महासभा के सदस्यों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी।

आप का आरोप- गोवा की सड़कें बेहद खराब, मुख्यमंत्री को भेजे गए एक लाख शिकायत पत्र

पणजी। आम आदमी पार्टी (आप) और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गोवा सरकार पर सड़कों की अनदेखी का आरोप लगाया। आप ने खराब सड़कों का मुद्दा उठाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को एक लाख शिकायत पत्र भेजे। इन चिट्ठियों में गोवा के नागरिकों के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। इनमें सड़कों की दुर्दशा पर नाराजगी जताई गई है। गोवा दौरे के अंतिम दिन केजरीवाल ने पार्टी कार्यालय के सामने एक टेंपो को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें ये सभी पत्र रखे गए थे। यह टेंपो मुख्यमंत्री सावंत के निवास की ओर भेजा गया, ताकि पत्र उन्हें सौंपे जा सकें। पत्रकारों से बातचीत में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, 'मुझे हमेशा बताया गया था कि गोवा की सड़कें खराब हैं, लेकिन अब मैंने खुद इस स्थिति का अनुभव किया है।' उन्होंने बताया कि अपनी यात्रा के पहले ही



सड़कों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भाजपा के बुरक नाम से अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत पार्टी को राज्य के एक लाख परिवारों से हस्ताक्षर मिलने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा, 'गोवा में साढ़े तीन लाख परिवार हैं, जिनमें से एक लाख ने इस अभियान पर हस्ताक्षर किए। यानी राज्य की एक तिहाई आबादी ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई है।'

बिहार चुनाव में बीजेपी का चेहरा बनेंगी मैथिली ठाकुर? तावड़े-राय से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल

पटना। प्रख्यात गायिका मैथिली ठाकुर ने भाजपा चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह दरभंगा की किसी सीट से भाजपा के टिकट और हार भागारी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। विनोद तावड़े ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर ये तस्वीरें साझा कीं। एक पोस्ट में, तावड़े ने कहा कि, जिनका परिवार 1995 में लालू प्रसाद



ठाकुर जी, बदलते बिहार को देखकर, बिहार लौटना चाहती हैं। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यराज राय जी और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के आम आदमी को उनसे योगदान की अपेक्षा है और वे उनकी अपेक्षाओं पर

कमल हासन ने करूर का किया दौरा, भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से की मुलाकात, पुलिस की प्रशंसा की

करूर । मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) प्रमुख और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने सोमवार को तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुई भगदड़ वाली जगह का दौरा किया, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। हासन ने इसे 'त्रासदी' बताते हुए कहा कि आयोजकों को दोष मढ़ने के बजाय जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। हासन ने अधिकारियों से बातचीत की और घटना से प्रभावित लोगों के परिवारों से मुलाकात की, जो अभिनेता और तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के संस्थापक विजय द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान हुई थी। हासन ने पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद पत्रकारों से कहा मामला अदालत में है और हमें इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोग पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं। हम यहाँ यह सुनिश्चित करने आए हैं कि उन्हें न्याय



का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा, 'यह एक अविस्मरणीय करकल होता।' उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने सम्मानपूर्वक काम किया और वे प्रशंसा के पात्र हैं। पुलिस का बचाव करते हुए, हासन ने जनता से आग्रह किया कि वे उन्हें अपना काम करने दें।

समीर वानखेड़े शराब लाइसेंस मामले, बॉम्बे एचसी ने मांगे अहम दस्तावेज

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर को नया नोटिस जारी किया। इस याचिका में वानखेड़े ने रद्द किए गए शराब लाइसेंस के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस ए एस गडकरी और आर आर भोंसले की खंडपीठ ने वानखेड़े को मामले में आगे बढ़ने से पहले, अब रद्द हो चुके शराब लाइसेंस की एक प्रति जमा करने का निर्देश दिया। यह लाइसेंस मूल रूप से उनकी मां के नाम पर जारी किया गया था और बाद में कथित तौर पर उन्हें नाबालिग के रूप में शामिल किया गया था। यह मामला नवी मुंबई के एक रेस्टोरेंट

के लिए शराब के लाइसेंस से जुड़ा है, जो शुरू में वानखेड़े की मां के नाम पर था। अधिकारियों का आरोप है कि



वानखेड़े का नाम उस समय पार्टनर के रूप में जोड़ा गया था जब वह नाबालिग थे। बाद में 2022 में लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। वानखेड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा और रिज़वान मर्चेंट ने तर्क दिया कि

एफआईआर प्रेरित थी और इसमें कानूनी आधार का अभाव था। पोंडा ने दलील दी कि वानखेड़े ने, जबकि उनकी उम्र

18 साल होने में अभी कुछ महीने बाकी थे, लाइसेंस के संबंध में एक हलफनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जो अब एफआईआर का आधार बन गया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित था, और इसे वानखेड़े की नारकोटिक्स कंट्रोल

ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पिछली भूमिका से जोड़ा, जिसके दौरान उन्होंने एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था। पोंडा ने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ लगातार अभियान चलाया था। पोंडा ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि वानखेड़े को 2022 में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था और तर्क दिया कि प्राथमिकी में लगाई गई धाराएँ इस मामले पर लागू नहीं होतीं। पीठ ने प्राथमिकी की जाँच के बाद, लाइसेंस में कथित रूप से शामिल किए जाने के समय वानखेड़े की उम्र पर सवाल उठाया। पोंडा ने जवाब दिया वह 17 साल से ऊपर का था, 18 साल से बस कुछ ही महीने छोटा। लाइसेंस वैध था और उसकी मां के नाम पर था। उनका कहना है कि जब वह नाबालिग था, तब उसकी मां ने उसका नाम इसमें जोड़ दिया था।

जेएसएल धोखाधड़ी: पुलिस के आचरण पर हाईकोर्ट के गंभीर सवाल, ईओडब्ल्यू से जांच छीनने का आदेश मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

जेएसएल रियल्टी मामले में कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एक जाँच अधिकारी को फटकार लगाने के बाद, जाँच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से मुंबई अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई है। यह स्थानांतरण आदेश महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किया गया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड़ की पीठ आईआईएफएल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने पाया कि वही जाँच अधिकारी, जिसे पहले गलत गिरफ्तारी के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, अभी भी मामले को देख रहा है। अदालत ने इससे पहले आरोपी ममता सिंह को अंतरिम राहत दी थी, जिन्हें आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 10 सितंबर को गिरफ्तार किया था।



किया कि सिंह को अपने दिव्यांग बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के दौरान क्यों गिरफ्तार किया गया और अन्य आरोपियों के विपरीत उन्हें आगे नोटिस क्यों नहीं दिए गए। पीठ ने कहा देरी से हुई गिरफ्तारी के कारणों को बताने में विफलता जांच के आचरण पर गंभीर

का अधिकार निरंकुश नहीं है और इसका प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(बी)(ग) के तहत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। आगे अपराध रोकने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी ज़रूरी होनी चाहिए।

रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को घायल करने के आरोप में दो गिरफ्तार मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बांद्रा रेलवे पुलिस ने सांताक्रूज रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को पीटकर घायल

घंटे के भीतर अपराध को सुलझा लिया है। शिकायतकर्ता, सतीश रामभुज प्रजापति (विक्रोली), सुबह के समय सांताक्रूज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर लोकल ट्रेन से उतर रहे थे, जब दोनों ने उन्हें पीटा

में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 115 (2), 118 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शाहजी निकम के मार्गदर्शन में बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों और



करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम नौशाद बिलाल अहमद और रामसूरत रामभरोसे राय हैं। घायल यात्री का नाम सतीश प्रजापति है। पुलिस ने इस संबंध में बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर 5

और सीने पर लात मारी। उनमें से दूसरे ने उनके माथे के बाईं ओर हरे रंग के कटर ब्लेड से उनके सिर पर मारा, जिससे उनके सिर में 6 टांके आए। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, तदनुसार बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन

अपराध जांच दल के कर्मचारियों ने महज 5 घंटे के भीतर आरोपी नौशाद बिलाल अहमद (शांति नगर, वडाला) और रामसूरत रामभरोसे राय (वडाला) का पता लगाकर अपराध को सुलझा लिया है।

मध्य रेल के महाप्रबंधक ने भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल, भायखला का दौरा किया मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री विजय कुमार ने 05.10.2025 को भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल, भायखला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चल रही गतिविधियों की समीक्षा की और अस्पताल के बुनियादी ढाँचे एवं स्वास्थ्य सेवाओं में नियोजित सुधारों पर चर्चा की। इस दौरान, उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और रोगी देखभाल के स्तर को ऊँचा उठाने के



उद्देश्य से प्रस्तावित सुधारों पर विस्तृत चर्चा की। अपने संबोधन में, महाप्रबंधक ने कहा कि अस्पताल की सुविधाओं और

कर्मचारियों के लाभों में वृद्धि सर्वाच्च प्राथमिकता है और उन्होंने अस्पताल सेवाओं में सुधार के लिए पूरे दिल से समर्थन का आश्वासन दिया।

उन्होंने अस्पताल के समग्र विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अस्पताल भवनों का उन्नयन शामिल है। इस अवसर पर मध्य रेल की प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक (पीसीएमडी) डॉ. ममता शर्मा, मुंबई मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री हिरेश मीना सहित विभिन्न विभागों के डॉक्टर और अधिकारी उपस्थित थे।

मध्य रेल

पॉलीयूरिया कोटिंग का प्रावधान (आपूर्ति और अनुप्रयोग)

ब्रेक वाल्व परीक्षण कक्षाओं के लिए शॉप फ्लोर क्षेत्र में पॉलीयूरिया कोटिंग का प्रावधान (आपूर्ति और अनुप्रयोग), मात्रा-700 वर्ग मीटर. उप मुख्य विद्युत अभियंता (ईएमयू) दूसरी मंजिल नवीन प्रशासकीय भवन, सवारी कारखाना, मध्य रेलवे, माटुंगा, मुंबई-19, ब्रेक वाल्व परीक्षण कक्षाओं के लिए शॉप फ्लोर क्षेत्र में पॉलीयूरिया कोटिंग का प्रावधान (आपूर्ति और अनुप्रयोग), मात्रा-700 वर्ग मीटर, कार्य के लिए इ-निविदा आमंत्रित करते हैं। अनुमानित लागत: ₹. 29,28,100/- ईएमडी: ₹. 58,600/- निविदा प्रपत्र शुल्क: शुल्य, समापन अवधि: 06 माह निविदा जमा करने की समाप्ति दिनांक एवं समय: 29.10.2025, 15:00 बजे। निविदा केवल इ-टेंडरिंग फॉर्मेट में वेबसाइट www.iareps.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे निविद पुस्तिका वेबसाइट पर उपलब्ध है। निविदा संख्या: ईएसटी/ईएमयू/एमटीएन/बीई/पॉलीयूरिया/03/06-2025

अनुसूचित तथा अनुसूचित रूप से रेत लाइन के पास कार्य करना दलील अपराध है

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाबालिग लड़की की शादी कराने की कोशिश के आरोप में सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। खिनावली पुलिस थाने के निरीक्षक नितिन खैरनार ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और जिला बाल एवं महिला कल्याण (डब्ल्यूसीडब्ल्यू) की टीम रविवार को शहापूर के शेनवे स्थित 17 वर्षीय लड़की के घर में उसके हल्दी समारोह में पहुंची।

खैरनार ने बताया कि लड़की के पिता, दूल्हा और उसके पिता तथा एक विवाह दलाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने



बताया कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू अधिकारी की शिकायत पर बाल विवाह निषेध

अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। श्रमजीवी संगठन के पदाधिकारी प्रकाश खोडका ने ऐसी घटनाओं के लिए गरीबी का हवाला दिया। उन्होंने ही इस मामले की सूचना पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया कि दूल्हे का परिवार दुल्हन के माता-पिता को कथित तौर पर 50,000 रुपये देने पर सहमत हो गया था।

स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत पश्चिम रेलवे द्वारा स्वच्छ स्टेशन एवं स्वच्छ रेलगाड़ी पर विशेष ध्यान मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, कारखानों और ट्रेनों में स्वच्छता, सफाई और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1 से 15 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मना रही है। इस अभियान के शुभारंभ और प्रारंभिक गतिविधियों के आधार पर तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन स्वच्छ स्टेशनों और स्वच्छ रेलगाड़ी पर केंद्रित पहलों के साथ अभियान आगे बढ़ा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार, 80 से अधिक प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों, परिसंचरण क्षेत्रों और यात्री सुविधाओं सहित सघन सफाई अभियान चलाया गया। 31 स्टेशनों पर उचित कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए सफाई मशीनों, औजारों, संयंत्रों और सुरक्षात्मक उपकरणों का निरीक्षण

किया गया। 123 स्टेशनों पर कूड़ेदानों और उनके रखरखाव का सत्यापन किया गया, जबकि 37 स्टेशनों पर नालियों, शौचालयों, पहुँच मार्गों, पैदल ऊपरी पुलों और प्रतीक्षालयों की व्यापक सफाई की गई। इसके अतिरिक्त, स्टेशनों पर चल रहे स्वच्छता अभियानों में सहयोग के लिए हाइड्रेंट पाइपों का निरीक्षण और उचित स्टैकिंग भी की गई। पर्यावरण-अनुकूल निपटान और पीईटी बोतलों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि से आठ प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनें (पीबीसीएम) लगाई गईं। हरित ऊर्जा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा उपकरणों के संचालन और रखरखाव की जाँच की गई। जैव-निम्मीकरणीय और अजैव-निम्मीकरणीय कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान लगाए गए और स्वच्छता बनाए रखने

और दुर्गंध को रोकने के लिए स्टेशनों पर नालियों और शौचालयों की व्यापक सफाई की गई। पाँचवें दिन, 5 अक्टूबर को, स्वच्छ रेलगाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया गया। ट्रेन वाशिंग लाइनों पर गहन सफाई अभियान चलाए गए, जिनमें शौचालयों, गैंगवे और वेस्टिबुल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया और 27 ट्रेनों की गहन सफाई की गई। अधिकारियों द्वारा लगभग 20 महत्वपूर्ण ट्रेनों का निरीक्षण किया गया, जिनमें पर्याप्त ओबीएचएस कर्मचारियों, लिनेन की गुणवत्ता और पैट्री कार की सफाई की जाँच की गई। यात्रियों को बायो-टॉयलेट, फ्लशिंग सिस्टम और ट्रेनों व स्टेशनों पर कूड़ा-कचरा न फैलाने की प्रथाओं के उचित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए कई स्थानों पर यात्री जागरूकता अभियान चलाए गए। इन निरंतर प्रयासों के माध्यम से पश्चिम रेलवे स्वच्छ भारत मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है तथा अपने नेटवर्क में यात्रियों और समुदायों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ स्टेशनों और ट्रेनों को सुनिश्चित करती है।

ठाणे के शहापूर में बाल विवाह नाकाम, चार गिरफ्तार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

खैरनार ने बताया कि लड़की के पिता, दूल्हा और उसके पिता तथा एक विवाह दलाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने

सवाल का जवाब केवल राज ठाकरे ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा, 'एमवीए का गठन तीन प्रमुख दलों से मिलकर हुआ था। मनसे एक स्वतंत्र पार्टी है। शिवसेना (यूबीटी) और मनसे (नगरीय निकाय चुनावों के लिए) के बीच चर्चा है। उन्होंने

जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर नगर निकाय की राजनीतिक स्थिति अलग होती है और स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में विभिन्न नगर निकायों के चुनाव इस साल के अंत तक होने की संभावना है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्रमांक-एचओ/ 1479 /ईपीआई दिनांक 06.10.2025

लोक स्वास्थ्य विभाग

रुचि व्यक्त करने हेतु विज्ञापन

विषय: लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एफ/एस वार्ड ए.एच.ओ. (ई.पी.आई.) में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संविदा के आधार पर श्रेणी 'डी' में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य विभाग के एफ/एस वार्ड में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (ई.पी.आई.) के रिक्त पदों को स्वैच्छिक संगठनों (बचत समूहों को छोड़कर) के माध्यम से संविदा के आधार पर भरने के लिए, केवल वे संगठन आवेदन करें जो बृहन्मुंबई नगर निगम के एफ/एस वार्ड में संविदा के आधार पर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इच्छुक संगठन भविष्य निधि राज्य और कर्मचारी बीमा योजना में पंजीकृत श्रमिक सहकारी समितियाँ, सेवा सहकारी समितियाँ, बेरोजगार सेवा सहकारी समितियाँ, गैर-सरकारी संगठन (इन सभी संगठनों की स्थापना का उद्देश्य अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान करना होना चाहिए) आदि हैं। हम संगठनों से उनकी पात्रता सूची तैयार करने और लॉटरी के माध्यम से उनका चयन करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं।

अधिक जानकारी, आवेदन पत्र और शपथ पत्र के लिए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (ईपीआई) विभाग से 07.10.2025 से 14.10.2025 तक सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक संस्थाएँ अधिक जानकारी, आवेदन पत्र और शपथ पत्र के लिए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (ईपीआई), एफ/एस वार्ड से संपर्क करें। संस्था के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14:10.2025, दोपहर 1:00 बजे तक है। निर्धारित कार्यालय समय के बाद जमा किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (ई.पी.आई.) (एफ/एस वार्ड)

पीआरओ/1807/विज्ञा./2025-26

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

स्वामीनाथन और टाटा फाउंडेशन के साथ समझौता राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास के नए युग का सूत्रपात- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि कृषि विभाग, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ग्रामीण विकास विभाग और टाटा मोटर्स के साथ हुए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन राज्य में कृषि, महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे।

सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए कृषि में नए प्रयोगों को प्राथमिकता दे रही है। महिला किसान कृषि व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं। उनकी भागीदारी से हम न केवल उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पोषण सुरक्षा समय की मांग है और यह पहल किसानों को लाभान्वित करने

के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा टाटा मोटर्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) ग्रामीण विकास को गति प्रदान



करेगा। इस समझौते के माध्यम से 63 ग्राम पंचायतों में प्रभावी कार्य हो सकेगा और भविष्य में इसके विस्तार के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। साथ ही, यह समझौता ज्ञापन ग्रामीण विकास विभाग के समृद्धि ग्राम मिशन को भी गति प्रदान करेगा। इन पहलों

के माध्यम से गाँवों के सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक सक्षम बुनियादी ढाँचा तैयार किया जाएगा।

कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य केवल खाद्य सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पोषण सुरक्षा,

पर्यावरणीय स्थिरता और किसान समृद्धि के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, बल्कि 'जैव-सुख' आधारित सतत एक रूपरेखा तैयार की जा सकेगी।

साथ ही, यह समझौता ज्ञापन ग्रामीण विकास विभाग के समृद्धि ग्राम मिशन को भी गति प्रदान करेगा। इन पहलों

पर्यावरणीय स्थिरता और किसान समृद्धि के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, बल्कि 'जैव-सुख' आधारित सतत एक रूपरेखा तैयार की जा सकेगी।

साथ ही, यह समझौता ज्ञापन ग्रामीण विकास विभाग के समृद्धि ग्राम मिशन को भी गति प्रदान करेगा। इन पहलों

भरणे, ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्य मंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. विकास चंद्र रस्तोगी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ दावले, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, टाटा मोटर्स के सीईओ विनोद कुलकर्णी आदि उपस्थित थे।

पर्यावरणीय परिवर्तनों और पोषण मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक और स्थानीय मोटे अनाजों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को महिला कृषक वर्ष घोषित किया है। इस अवसर पर महिला कृषकों के सशक्तिकरण हेतु एक कानून बनाया गया है। साथ ही, सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण मिशन की स्थापना भी की गई है।

पर्यावरण के अनुकूल, पौष्टिक और जैव विविधता को बढ़ावा देने वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में जैव-सुख केंद्रों की स्थापना। पालघर जिले की छह ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल

क्रियान्वयन के बाद, यह कार्यक्रम राज्य भर की 63 ग्राम पंचायतों (100 गाँवों) में क्रियान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान का पूरक है। यह कार्यक्रम राज्य के 10 आकांक्षी तालुकों में क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तीन वर्षीय कार्यक्रम अवधि के दौरान प्रत्येक चयनित गाँव में ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से गाँवों का सतत विकास करना है। कार्यक्रम अवधि के अंत तक, संबंधित गाँवों के सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाएगा। यह कार्यक्रम विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ टाटा मोटर्स के सामाजिक उत्तरदायित्व कोष के अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व कोष का उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

ग्रामीण विकास योजनाएं तैयार करने तथा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

नवी मुंबई नगर निगम लोकतंत्र दिवस का आयोजन मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र सरकार के निर्देशानुसार, नवी मुंबई नगर निगम स्तर पर प्रत्येक माह के पहले सोमवार को नवी मुंबई नगर निगम मुख्यालय में लोकशाही दिवस का आयोजन किया जाता है।

नवंबर माह का लोकशाही दिवस दिनांक: 03 नवंबर 2025 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में जमा करने होंगे। दिनांक: 17 अक्टूबर 2025 माननीय आयुक्त, नवी मुंबई नगर निगम के नाम 'लोकशाही दिवस के लिए आवेदन' ऐसे दृश्य पहलुओं को उजागर करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नवी मुंबई नगर निगम से लोकशाही दिवस के लिए निर्धारित आवेदन पत्र 'हस्स्क्रिप्ट' रह इस वेबसाइट (वेबसाइट) होम पेज त्वरित लिंक आवेदन पत्र आइकन पर उपलब्ध है और इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसी प्रकार, नगर निगम के नए मुख्यालय भवन, जनसंपर्क विभाग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 15 ए, किला गाँव के पास, सी.बी.डी., बेलपुर में नागरिकों के लिए एक प्रति निःशुल्क

उपलब्ध है।

आवेदन करने समय, नागरिकों को सरकारी निर्णय के अनुसार आवेदन में उल्लिखित शिकायत का उल्लेख करना चाहिए। / कथन व्यक्तिगत प्रकृति का होना चाहिए। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। आवेदन एक ही विभाग से संबंधित एक ही विषय के लिए होना चाहिए। आवेदक को संबंधित विषय के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। प्रथम श्रेणी के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा शिकायत / यदि कथन व्यक्तिगत प्रकृति का नहीं है, और अंतिम उत्तर पहले ही दिया जा चुका है / दिया जाना है तो नागरिकों को यह भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि उसी विषय के संबंध में दोबारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल

शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और संतुलित बनाने के लिए, वुलाधिपति एवं राज्यपाल कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि इसी प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च



विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा के मानक को बनाए रखने हेतु आवश्यक

प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं।

उपाय और प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। इस अधिसूचना के प्रावधानों को राज्य में लागू कर दिया गया है। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के संचालन की प्रक्रिया 28 फरवरी 2025 के सरकारी निर्णय

के अनुसार निर्धारित की गई थी। इस चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और संतुलित बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।

सरकारी गैर-वृषि विश्वविद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक और वैधानिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया नई प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जाएगी और भविष्य की सभी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए इसी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा, मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा।

इस संबंध में सरकारी निर्णय की घोषणा www.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर की गई है।

आधुनिक सिनेमा सिटी की स्थापना से नासिक के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा - उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

विशेषज्ञ सलाहकारों की रिपोर्ट के बाद व्यवहार्यता की जाँच कर तुरंत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक मनोरंजन केंद्र बनाने का विजन प्रस्तुत किया है। इस लक्ष्य के साथ कि महाराष्ट्र इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए, नासिक सिनेमा सिटी परियोजना निर्णायक साबित होगी। इस परियोजना से स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों, लघु उद्योगों, होटल व्यवसाय, पर्यटन, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने विश्वास व्यक्त किया कि नासिक के समग्र आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति मिलेगी। सरकार नासिक में सिनेमा उद्योग स्थापित करने के प्रति सकारात्मक है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए नियुक्त विशेषज्ञ सलाहकारों की रिपोर्ट के बाद व्यवहार्यता की जाँच कर तुरंत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश

दिए।

नासिक सिनेमा सिटी परियोजना के संबंध में एक बैठक सह्याद्री अतिथि

गुप्ता, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खडगे, नियोजन विभाग के प्रधान सचिव सौरभ विजय,



गृह में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छान भुजबल, टेलीकांफ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी.

उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सांस्कृतिक मामलों के सचिव किष्ण कुलकर्णी, महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल की प्रबंध निदेशक स्वाति म्हसे-पाटिल, टेलीकांफ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से नासिक के संभागीय

आयुक्त प्रवीण गेडाम, नासिक के जिला कलेक्टर जलज शर्मा सहित फिल्म क्षेत्र से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि नासिक भारतीय सिनेमा के जनक दादासाहेब फाल्के की जन्मभूमि है। इसलिए नासिक में फिल्म उद्योग की स्थापना न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजमार्गों, रेलवे, हवाई परिवहन और कुंभ मेले द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं के कारण नासिक चित्रनगरी के निर्माण के लिए आदर्श है। इस परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ परामर्शदाता फर्म को नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद, उसके निष्कर्षों के आधार पर एक अद्यतन प्रस्ताव तैयार किया जाए।

नागरिकों को सहकारी सेवाएँ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सेवाओं में तेज़ी लाई जाए - सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल

सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने मुंबई विभाग की समीक्षा की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने सहकारिता विभाग से संबंधित सेवाओं को आम जनता तक आसानी से और सुविधाजनक ढंग से पहुँचाने के लिए सहकारिता विभाग से संबंधित अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मल्होत्रा हाउस में सहकारिता मंत्री

बाबासाहेब पाटिल की अध्यक्षता में मुंबई विभाग की समीक्षा की गई। इससे नागरिकों को समय पर सेवाएँ देना कठिन है। प्रशासनिक कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाने आवश्यक हैं। नागरिकों को समय पर सेवाएँ मिलें, ताकि उन्हें देरी से परेशानी न उठानी पड़े। विभाग स्तर पर नागरिकों की कई शिकायतें सीधे मंत्रालय में आ रही हैं। हमारे विभाग के कार्यों की समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए और नागरिकों के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कार्यों में ई-ऑफिस का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने कहा कि प्रशासनिक कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाने आवश्यक हैं। नागरिकों को समय पर सेवाएँ मिलें, ताकि उन्हें देरी से परेशानी न उठानी पड़े। विभाग स्तर पर नागरिकों की कई शिकायतें सीधे मंत्रालय में आ रही हैं। हमारे विभाग के कार्यों की समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए और नागरिकों के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिकायतों, शहरी सहकारी बैंकों के लंबित कामकाज की समीक्षा, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को समीक्षा और संभागीय संयुक्त पंजीयक के पास लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में संभागीय संयुक्त पंजीयक शाहजी पाटिल, जिला उप पंजीयक निनिन काले, किरण सोनवणे, आनंद कटके, राजेश लाडकेकर और मुंबई संभाग के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी तथा संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। पिछले साल से पुलिस के परिमंडल 6 के पुलिस स्टेशनों की ओर से नाश विरोधी अभियान चलाया गया है। अब तक करोड़ों रुपये की ह्रास और इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के तहत, क्राइम इंटेलिजेंस टीम पुलिस ने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गश्त के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 80,000 रुपये मूल्य की 40 ग्राम एमडी जब्त की है।

मुख्बिर के जरिए गुप्त सूचना मिली थी कि ये दोनों आरोपी एमडी ड्रग बेचने के लिए ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आ रहे हैं। तदनुसार, क्राइम इंटेलिजेंस टीम को गिरफ्तार कर लिया। उस समय, उनके पास बिक्री के लिए लाया गया ड्रग एमडी पाया गया। पुलिस ने अब उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट, 1985 की धारा 8 (सी), 21, 29 के तहत मामला दर्ज किया है। इस अपराध में गिरफ्तार लोगों के नाम मोहम्मद फैज अली खान (चिता कैंप, ट्रॉम्बे) और जाहिद जहांगीर अली शेख (चिता कैंप, ट्रॉम्बे) हैं।

गिरफ्तार आरोपी एक अपराधी और ड्रग पैडलर है और उसके खिलाफ पहले भी कई तरह के अपराध दर्ज हैं। अब इस अपराध की आगे की जांच अधिकारी शरद नानेकर कर रहे हैं।

यह कार्रवाई पूर्व प्रादेशिक विभाग अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेश पाटिल, पुलिस उपायुक्त समीर शेख, सहायक पुलिस आयुक्त राजेश बाबशेडी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ऋता नेमलेकर के मार्गदर्शन में अधिकारी सुशील लोढे, शरद नानेकर, धूमाल, आल्हाड, पाटिल, पवार, आटपाडकर ने यह काम किया है।

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर अपग्रेडेशन कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर 25 नवंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक चल रहे अपग्रेडेशन कार्य के मद्देनजर पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी।

अधिकार रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

निरस्त होने वाली ट्रेनें:-

- 30 नवंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09043 बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी स्पेशल
- 1 दिसंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09044 बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल

- 30 नवंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 05560 उधना-रक्सौल स्पेशल
- 29 नवंबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:-
- 29 नवंबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल-कटिहार स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर-कटनी मुरवारा-बीना स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
- 25 नवंबर, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09190 कटिहार-मुंबई सेंट्रल स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया बीना-कटनी मुरवारा-मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
- 25 नवंबर, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 04156 उधना-सूबेदारगंज स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया इटारसी-सतना-मानिकपुर-प्रयागराज स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
- 26 नवंबर, 2025 से 07 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 04156 उधना-सूबेदारगंज स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया इटारसी-सतना-मानिकपुर-प्रयागराज स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।

- 01 दिसंबर, 2025 से 05 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 04155 सूबेदारगंज-उधना स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया प्रयागराज-मानिकपुर-सतना-इटारसी स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
- 28 नवंबर, 2025 से 02 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया गुना-वालिपर-इटावा-कानपुर सेंट्रल स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
- 01 दिसंबर, 2025 से 05 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल-इटावा-वालिपर-गुना स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
- 26 नवंबर, 2025 से 07 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया वालिपर-गुना-बीना स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।

राज्य में 75,000 प्रशिक्षुओं को मिलेगा नए ज़माने के कौशल का प्रशिक्षण- मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ‘अल्पकालिक रोज़गारपरक पाठ्यक्रमों’ के एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। कौशल, रोज़गार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग युवाओं को उद्योग-संबंधित और रोज़गार-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल 'अल्पकालिक रोज़गारपरक पाठ्यक्रम' लागू कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर, 2025 को ऑनलाइन करेंगे, यह जानकारी कौशल, रोज़गार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने मंत्रालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी। इस पहल के उद्घाटन के अवसर पर, राज्य भर में 600 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और विश्वकर्मा समुदाय के कार्यगर्ों, स्थानीय कलाकारों



जाएगा और समाज में पारंपरिक कौशल का सम्मान बढ़ेगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 419 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

और 141 राजकीय तकनीकी विद्यालयों में कुल 2,506 इकाइयाँ शुरू की जाएँगी। इसके माध्यम से चालू वर्ष में 75,000 प्रशिक्षुओं को रोजगारपरक कौशल

माध्यम से कौशल शिक्षा का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और पाठ्यक्रमों का चयन स्थानीय माँग और जनहित के अनुसार किया गया है। प्रत्येक जिले में संस्था प्रबंधन समितियाँ स्थानीय स्तर पर इस पाठ्यक्रमों का संचालन करेंगी। इनसे शिक्षा के नियंत्रण, कार्यान्वयन और गुणवत्ता नियंत्रण के सभी पहलुओं में स्थानीय भागीदारी और जवाबदेही बढ़ेगी।

मंत्री लोढ़ा ने कहा, 'इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को उद्योग की बदलती माँगों को अनुसार आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल की विशेषता स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिला अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।'

सम्पादकीय

ज्यादातर शर्तें इजराइल के पक्ष में हैं इसलिए बनी बात, गाजा पर हो रहे हमले होंगे समाप्त, हमास भी अमेरिका की बात मानने पर हो गया तैयार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीस सूत्री शांति योजना की कुछ शर्तों पर हमास की ओर से सहमति जताना वास्तव में महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। इसे गाजा में शांति कायम होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल पहले ही इस योजना पर आगे बढ़ने को लेकर अपनी इच्छा जता चुका है। अब इजराइली सेना ने कहा है कि वह इस योजना के पहले चरण के लिए तैयारियां तेज करेगी। मगर, इजराइल की ओर से शनिवार को गाजा पर फिर हमला किए जाने की खबरों ने शांति के इन प्रयासों की राह में विरोधाभास पैदा कर दिया है।

यह तब हुआ है, जब हमास की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका ने इजराइल को गाजा पर हमले तुरंत रोकने को कहा। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि इस ताजा हमले के पीछे स्थानीय कारण हो सकते हैं और इसे शांति के मार्ग में बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मगर, ऊहापोह की इस स्थिति में इतना तय है कि अगर इजराइल और हमास एक-दूसरे पर फिलहाल हमले बंद करने का सैद्धांतिक तौर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, तो इस योजना पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा।

अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास ने अपने बयान में कहा है कि वह बंधकों को रिहा करने और सत्ता अन्य फिलिस्तीनियों को सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि, इस बयान में हमास के हथियार डालने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो अमेरिकी प्रस्ताव में शामिल इजराइल की एक प्रमुख मांग थी। इसके साथ ही हमास ने प्रस्ताव की अन्य शर्तों पर कहा है कि इन्हें लेकर संगठन के भीतर कुछ विरोधाभास हैं, जिन पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है।

यानी हमास अभी इस प्रस्ताव पर पूरी तरह सहमत नहीं है। जाहिर है कि वह किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले प्रमुख शर्तों के तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभावों और आशंकाओं का आकलन करना चाहता है। अब सवाल यह है कि इजराइल ने बिना देर किए अमेरिकी प्रस्ताव पर तत्काल सहमति कैसे और क्यों जता दी! इसका जवाब प्रस्ताव की शर्तों में ही छिपा है। माना जा रहा है कि ज्यादातर शर्तें इजराइल के पक्ष में हैं और जहां उसे संदेह है, वहां कोई बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश बनी रहेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गाजा में शांति की इस पहल को एक अवसर के रूप लिया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को इस पर बिना किसी संकोच के आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी तुरंत नहीं रोकी, तो शांति की कोशिशें पटरी से उतर सकती हैं।

ऐसे में जानकारी का कहना है कि इस तरह के हमले जारी रहने से शांति योजना को जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि दोनों पक्षों की ओर से धैर्य और संयम बरता जाए। इजराइल और हमास के बीच करीब दो वर्षों से जारी युद्ध में मरने वालों की संख्या 67, 000 से अधिक हो गई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसलिए जरूरी है कि मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखकर इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं।



चंद्र विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम

हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ‘शरद पूर्णिमा’ पर्व मनाया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में आसमान में चमकता है। इस वर्ष यह पावन तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 23 मिनट से आरंभ होकर 7 अक्टूबर की सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगी, इसलिए शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की रात को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा के पूर्ण स्वरूप का उत्सव भी कहा जाता है। इस रात चंद्रमा की रोशनी इतनी तेज होती है कि धरती दूधिया उजास में नहा उठती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष रूप से औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। यह माना जाता है कि इन किरणों में स्वास्थ्य, सौंदर्य और शक्ति बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। वेदों और पुराणों में चंद्रमा को औषधियों का स्वामी माना गया है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि ‘मैं ही सोम रूप चंद्रमा बनाकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूं।’

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्षभर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी सभी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है। माना जाता है कि प्रत्येक कला मनुष्य के जीवन की किसी न किसी विशेषता का प्रतीक होती है। भगवान श्रीकृष्ण को इन सोलह कलाओं का पूर्ण रूप कहा गया

है, इसलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी रात श्रीकृष्ण ने अपनी मुरली की मधुर धुन पर ब्रज की गोपियों के साथ यमुना तट पर दिव्य महारास किया था। इसीलिए यह रात प्रेम, आनंद और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वृंदावन और बृज क्षेत्र में आज भी शरद पूर्णिमा को बहुत उत्साह से मनाया जाता है।

शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कौमुदी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ‘कोजागर’ का अर्थ है ‘कौन जाग रहा है?’ मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी को शोशनी भेंट की जाती है। वृंदावन और बृज क्षेत्र में आज भी शरद पूर्णिमा को बहुत उत्साह से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कौमुदी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ‘कोजागर’ का अर्थ है ‘कौन जाग रहा है?’ मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी को शोशनी भेंट की जाती है। वृंदावन और बृज क्षेत्र में आज भी शरद पूर्णिमा को बहुत उत्साह से मनाया जाता है।

शरद पूर्णिमा की रात का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर प्रतीक है खीर की परंपरा। इस रात घरों

में खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे रखी जाती है ताकि चंद्रमा की चांदनी उसमें पड़े। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है और वह अमृत खीर में समा जाता है। सुबह उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो अमृत समान मानी जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से दूध, चावल और चीनी चंद्र ग्रह से जुड़े तत्व हैं। इसीलिए चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर में उसकी शुभ ऊर्जा और औषधीय गुण समा जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस परंपरा का गहरा अर्थ है। दूध में लैक्टिक एसिड और खीर में मौजूद चावल के स्टार्च के कारण जब इसे खुली चांदनी में रखा जाता है तो उसमें ऐसे परिवर्तन होते हैं, जो इसे अधिक पौष्टिक बना देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की किरणों में मौजूद अल्ट्रा-वायलेट और इंफ्रारेड ऊर्जा दूध में मौजूद सूक्ष्म जीवों की क्रिया को सक्रिय करती है, जिससे वह पाचन में सहायक और स्वास्थ्यवर्धक बन जाता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात रखी खीर को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण इस रात दर्पण के माध्यम से चंद्रमा की किरणों को अपनी नाभि पर ग्रहण कर युवा शक्ति प्राप्त करता था। यह कथा प्रतीक है कि चंद्रमा की किरणें शरीर में ऊर्जा, शांति

और जीवन शक्ति भरने का सामर्थ्य रखती हैं। शरद पूर्णिमा ऋतु परिवर्तन की भी प्रतीक है। यह दिन वर्षा ऋतु की समाप्ति और शीत ऋतु के आगमन की घोषणा करता है। मौसम बदलने के इस समय शरीर को नई जलवायु के अनुकूल बनाना आवश्यक होता है। आयुर्वेद के अनुसार, इस समय वात, पित्त और कफ दोषों में असंतुलन की संभावना बढ़ती है। खीर का मधुर स्वाद और संतुलित शरीर प्रभाव इन दोषों को संतुलित करने में सहायक होता है। इसलिए यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शरद पूर्णिमा की रात का सौंदर्य अद्भुत होता है। जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में अपनी सोलह कलाओं के साथ दमकता है तो उसकी दूधिया रोशनी में पूरी धरती जैसे अमृत में डूब जाती है। इस दृश्य को देखकर मन में स्वतः शांति और प्रसन्नता का संचार होता है। यह रात केवल पूजा या जागरण की नहीं बल्कि आत्म-शुद्धि और ध्यान की भी होती है। यह दिव्य पर्व हमें संदेश देता है कि जैसे चंद्रमा अंधकार को मिटाकर जग को उजला देता है, वैसे ही हमें अपने भीतर की अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान और करुणा का प्रकाश फैलाना चाहिए। यह पर्व केवल बाहरी चंद्रमा का नहीं बल्कि हमारे भीतर के चंद्र स्वरूप (शीतलता, शांति और प्रेम) का भी उत्सव है।

नाचते नाचते दुनिया पर टैरिफ ठोकने वाले ट्रंप को अब मोदी जिनपिंग दिखाएंगे- हाथी-ड्रैगन का डांस

बीते कई दिनों से हम लगातार अमेरिकी टैरिफ से उपजे संकट की बात कर रहे हैं। अब ये साफ होता जा रहा है कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका की तरफ से कभी एचा।बी वीजा को लेकर बयान आता है। कभी पीट नवारी रूस-यूक्रेन युद्ध को मोदी का वॉर कह देते हैं। अमेरिका से मायूस हिंदुस्तान अब पूरब से उम्मीद लगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। चीन के साथ भी अमेरिका की ट्रेड वॉरनुमा स्थिति बनी हुई है। भले ही उसमें एक वक्ती समझौते से कुछ होख़्द लगा हो। लेकिन ट्रेड वॉर जैसी स्थिति तो चल ही रही है। वाशिंगटन से रिश्ते तख़्त हैं तो दिल्ली और बीजिंग के पास एक दूसरे के भारत आने के लिए एक वजह और जुड़ गई। 31 अप्रस्त को प्रधानमंत्री मोदी सात साल बाद चीन दौरे पर तियांनजिन पहुंचे। पीएम शंघाई कॉन्फ़रेंशन ऑर्गनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे थे। इस बैठक से इतर पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। साल 2020 में हुए गलवान संघर्ष, सीमा पर जारी विवाद और अमेरिकी टैरिफ के बीच मोदी-जिनपिंग की मुलाकात को काफी अहम माना गया।

चीन के बयान के मुताबिक चीन और भारत दुनिया की पुरानी सभ्यताएं हैं। दोनों के उपर अपने देश के लोगों के अलगवा, विकासशील देशों की एकाता की भी जिम्मेदारी है। अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बनना दोनों के लिए सही चुनाव होना चाहिए। इससे ड्रैगन और हाथी का डांस साईबै बन पाए। उन्होंने कहा कि दोनों देशो को अपने रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नज़रिए से देखना होगा। बहुपक्षवाद वे साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय से संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण के लिए अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। ड्रैगन के साथ आने की संभावना रेखांकित की जाने लगी है। लेकिन उसके लिए अभी दोनों देशों को लंबी दूरी तय करनी होगी, बहुत सारे मतभेद और विवाद दूर करने होंगे। इसका अंदाजा दोनों पक्षों को है। तभी बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि मतभेद झगड़े में तब्दील नहीं होने चाहिए।

पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात एससीओ का शो स्टॉपर रही। पहले दिन की हाईलाइट यही भेंट रही। खास बात है कि दोनों नेताओं की गर्मजोशी से मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को साफ मैसेज है कि दुनिया उनकी धुन पर नहीं नाचती। ट्रम्प खुद को ‘डोलमेकर’ बताते नहीं थक रहे, लेकिन अब तक उनके खाते में कोई

डील ही नहीं है। भारत और चीन ने ट्रम्प को कूटनीतिक जवाब दिया है। दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए पहल की है।

पीएम मोदी ने अगले साल भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति शी को न्योता दिया। उन्होंने चीन के एससीओ की सफलतापूर्वक अध्यक्षता किए जाने के लिए शी को बधाई भी दी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने ब्रिक्स में आने के लिए निमंत्रण देने पर मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन की पेशकश की।

मोदी और जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट्स और वीजा प्रक्रिया के जरिए लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत दिशा दिे जाने की भी वकालत की। कुछ हफ्ते में यह बहाल हो जाएंगी। इस साल गर्मियों में बहाल की गई कैलाश मानसरोवर यात्रा और ट्रैव्स्ट वीजा का जिक्र करते हुए दोनों नेताओं ने माना कि दोनों के आर्थिक रिश्ते दुनिया के व्यापार को स्थिर करने की क्षमता रखते हैं।

अमेरिका से टैरिफ के सवाल पर तनाव बढ़ने के कारण भारत और चीन करीब आ रहे हैं, बस इतना कहने भर देना बेहानी होगा। सच यही है कि गलवान झड़प के रूप में

आई एक बड़ी अड़चन के बाद भी दोनों देशों ने बातचीत के जरिए गलतफ़हमियां और मतभेद दूर करने की कोशिश नहीं छोड़ी। इस निरंतर प्रयास का ही नतीजा है कि धीरे-धीरे मतभेद कम होते रहे और पिछले साल सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के हिंसईंजमेंट को लेकर भी सहमति बन गई। रविवार की बैठक में दोनों नेताओं ने इस पर संतोष ज़ाहिर किया कि पिछले साल कजान में हुई शिखर बैठक में दोनों देशों के रिश्तों में लगातार सुधार जारी रहा।

पावर बैलेंस और भारत-चीन संबंधों को लेकर अब दुनियाभर में चर्चा हो रही है। चीन को लेकर हमेशा मन में आशंका की संभावना बनी रहती है। लेकिन फ़िल्हाल मौजूदा परिस्थिति को देखें तो दोनों एक दूसरे के प्रति भरोसा जताने के वादे करते नजर आ रहे हैं। दोनों देश दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ती हैं। अबदी के लिहाज से भी मैनपॉवर में सबसे आगे हैं। ऐसे में अमेरिका की गतिविधियां भारत-चीन को साथ आने का तर्कसंगत विकल्प दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप की पॉलिसी, अमेरिका के टैरिफ वॉर की सनक ने पावर बैलेंस में अहम बदलाव लाने की संभावनाओं को जन्म दिया है।

पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेलेी ने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ बातचीत करते रूस से तेल ख़रीद के मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए।

जनता को किया वोटिंग से किनारा, विपक्ष ने नकारा इस मुल्क के चुनाव को क्यों बताया जा रहा मजाक?

एक ऐसा चुनाव जिसमें शायद किसी बदलाव की उम्मीद नहीं। सीरिया में संसदीय चुनाव हुए। देश के लंबे समय से निरंकुश नेता बशार अल-असद के विद्रोही आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। असद वंश के 50 साल के शासन के दौरान, सीरिया में नियमित चुनाव होते थे जिनमें सभी नागरिक मतदान कर सकते थे। हालाँकि, असद के नेतृत्व वाली बाथ पार्टी का संसद पर दबदबा था और मतदान को व्यापक रूप से दिखावटी चुनाव माना जाता था। सीरिया के लोग चुनाव के बाद भी पूर्ण लोकतंत्र से चूक जाएंगे। सीरिया में हुए इस पहले चुनाव पर विवाद भी हो रहा है। वह इसलिए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहे हैं। इसमें जनता ने वोट नहीं डाला है। आलोचकों का कहना है कि इससे सत्ता के सीरिया के नए शासकों के हाथों में ही केंद्रित रहने की संभावना है। पीपुल्स असेंबली की अधिकांश सीटें जिलों के निर्वाचक मंडलों द्वारा चुनी जाएंगी, जबकि एक-तिहाई सीटों पर अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा नियुक्त होंगे। नई संसद भविष्य के चुनावों की तैयारी करते हुए 30 महीने का कार्यकाल पूरा करेगी।

सीरिया की नई संसद में 210 सदस्य हैं। इनमें से 140 सीटों पर 7, 000 इलेक्टोरल कॉलेज

सदस्य मतदान कर रहे हैं। ये सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। शेष 70 सदस्य अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा सीधे नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति शारा द्वारा नियुक्त 70 सीटों के जरिए



महिलाओं, अल्पसंख्यकों और सहयोगी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है, पर आलोचकों के मुताबिक यही सीटें सरकार की स्थायी बहुमत सुनिश्चित करेंगी। मतदान 5 अक्टूबर को हुआ। अंतिम परिणाम 7 अक्टूबर अंसंभव है। इसलिए अभी आम लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला है। सीधे जनमत कराने की

से भरी जाने के कारण संसद में शारा समर्थकों की निर्णायक जीत तय मानी जा रही है।

उम्मीद थी कि जब चुनाव होंगे तो जनता भी वोट डालेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतरिम सरकार

बजाय यह सीमित प्रक्रिया अपनाई गई है। आलोचकों ने लोकप्रिय वोट के अभाव को अलोकतांत्रिक बताया है, हालाँकि कुछ विश्लेषक सरकार के तर्क को सही मानते हैं। अरब रिफॉर्म इनिशिएटिव और चैथम

हाउस के वरिष्ठ शोध अध्येता ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचकों के चुनाव के तरीके में स्पष्टता का अभाव है। उन्होंने कहा खासकर जब उपसमितियों और निर्वाचक मंडलों के चुनाव की बात आती है, तो कोई निगरानी नहीं होती, और यह प्रक्रिया संभावित रूप से हेरफेर की चपेट में है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव अधिकारियों ने बिना किसी

स्पष्टीकरण के प्रकाशित सूचियों से नाम हटा दिए, जिससे आलोचनाएँ बढ़ गईं।

संसद में महिलाओं या धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों के लिए कोई निश्चित कोटा नहीं है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों में महिलाओं की संख्या 20इ होनी चाहिए, लेकिन इससे उम्मीदवारों या निर्वाचित सदस्यों के बीच समान प्रतिशत की गारंटी नहीं मिलती। सरकारी समाचार एजेंसी एँ के अनुसार, राष्ट्रीय चुनाव समिति के प्रमुख मोहम्मद ताहा अल-अहमद के हवाले से, अंतिम सूची में शामिल 1, 578 उम्मीदवारों में से 14इ महिलाएँ हैं। कुछ ज़िलों में, 30-40इ महिलाएँ उम्मीदवार हैं, जबकि अन्य में एक भी नहीं है। स्वीडा और कुर्द-नियंत्रित क्षेत्रों को बाहर रखे जाने से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा में अलावी और डूज़ समुदायों के सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से कई की मौत सरकार से जुड़े लड़ाकों के हाथों हुई है।

हायात तहरीर अल-शाम (एचटीएस): उत्तर-पश्चिमी सीरिया में सक्रिय याह संगठन चुनावों को ‘दमिश्क की सत्ता का नाटक’ बता रहा है। उसका कहना है कि अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की सरकार देश के वास्तविक प्रतिनिधित्व से कोसों दूर है, क्योंकि उसने जनता को वोट का अधिकार ही नहीं दिया।

वहीं असद समर्थक गुट बशार अल-असद की पार्टी ने इसे ‘कठपुतली चुनाव’ कहा है। उनका आरोप है कि शरा सिर्फ पश्चिमी देशों की मदद से सत्ता में आया और अब वैधता साबित करने के लिए दिखावटी प्रक्रिया चला रहा है।

रूस और चीन: दोनों देशों ने इन चुनावों को सीरिया की स्थिरता की दिशा में आवश्यक कदम बताया है। उनका कहना है कि युद्धग्रस्त देश में तुरंत जनमत संग्रह असंभव है, इसलिए अंतरिम संरचना ही व्यावहारिक विकल्प है। ईरान ने शारा सरकार को सीरिया के पुनर्निर्माण का केंद्र मानते हुए कहा कि चुनाव देश में राजनीतिक निरंतरता की गारंटी हैं और विपक्ष को समय के साथ शामिल किया जाएगा।

अभी भी पीपुल्स असेंबली की 32 सीटें खाली ही रहेंगी। वह इसलिए क्योंकि सीरिया के सुवेदा और उत्तर-पूर्वी प्रांत में वोटिंग नहीं हुई। इन प्रांतों में कुर्दिश लड़ाकों का दबदबा है। इसलिए अभी यहां वोटिंग नहीं करवाई गई है। कुल मिलाकर, 210 सीटों में से 178 सदस्यों के साथ सीरिया की सरकार चलेगी। सोमवार या मंगलवार तक चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। नई संसद के लिए जिन सदस्यों को चुना जाएगा, उनका कार्यकाल 30 महीने का होगा। ऐसा इसलिए ताकि चुनाव तैयारियों के लिए समय मिल सके। बताया जा रहा है कि इसके बाद आम चुनाव कराए जा सकते हैं।

अब फिल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर चिपकाई जाती है चेहरे की मुस्कान, बिना किसी उपलब्धि के भी खुश रहना एक कला

हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं, विज्ञान के नियम और अंग्रेजी के शब्द रचवाते हैं। हम उन्हें मोबाइल चलाना सिखा देते हैं। इसके बाद उन्हें बैंक से जुड़ी गतिविधियों के लिए एप डाउनलोड करना आ जाता है, कैलकुलेटर पर बड़ी से बड़ी गणना करने में वे माहिर हो जाते हैं। वे सोशल मीडिया के सभी मुख्य मुद्दों के बारे में जानते हैं। वे एक विलक में फोटो को संपादित करके उसे अपने मन के मुताबिक बना सकते हैं, आनलाइन आवेदन भर सकते हैं।

मगर क्या कभी हमने उन्हें खुश रहना सिखाया है या उन्होंने कहीं से सीखा है? या फिर खुशी की किसी अंधेरी दुनिया में गुम हो रहे हैं? क्या हमने उन्हें यह बताया है कि दुख को स्वीकार कैसे किया जाता है या हार को अपमान नहीं समझा जाता? हर दिन जीत का दिन नहीं होता, लेकिन हर दिन जीने लायक हो सकता है? अगर मन का मौसम बदला-बदला हो, तो भी जिंदगी

को पकड़े रहना जरूरी है। हमारी शिक्षा और परवरिश, हमारे सारे संसाधन आज इस बात पर केंद्रित हैं कि बच्चा सफल हो, श्रेष्ठ बने, तेज दौड़े, दुनिया से आगे निकले। मगर कोई यह नहीं सिखाता कि अगर कभी थक जाओ, तो रुक जाना भी ठीक है, अगर मन उदास हो, तो चुप बैठना भी चलता है और सबसे जरूरी- बिना किसी उपलब्धि के भी खुश रहना एक कला है।

आज की पीढ़ी सब कुछ जानती है, लेकिन भीतर से अक्सर खाली है। उनके पास ब्रांडेड कपड़ों से भरी अलमारियां हैं, कमरे में सजावटी रोशनी और स्मार्ट स्क्रीन हैं, लेकिन चेहरों पर मुस्कान सिर्फ तस्वीरों के लिए होती है। जो हंसी पहले गली में दौड़ते हुए फूटती थी, वह अब फिल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर चिपकाई जाती है। बच्चों के पास अब हर जानकारी है, लेकिन जीवन की समझ नहीं। वे क्या चाहते हैं, यह तय करने से पहले ही उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें क्या बनना है। उनका

बचपन ‘करियर बनाने’ की दौड़ में बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। उनके चेहरे पर चिंता है, आंखों में थकावट है, और होठों पर ‘सब ठीक है’ का नकाब। जब कोई पूछता है- ‘कैसे हो?’ तो उत्तर आता है- ‘ठीक हूं। इस ‘ठीक’ के पीछे कितना अस्वस्थ होना, कितनी उलझन, कितना अकेलापन छिपा है, यह किसी को नहीं दिखता। हमने बच्चों से ‘अच्छा’ बनना तो मांगा, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं बताया कि अच्छा दिखने की नहीं, अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। यह महसूस करना तब आता है, जब हम भीतर से सहज हों। जीवन में सुख-दुख साथ-साथ चलते हैं, पर हमने उन्हें सिर्फ सफलता का पाठ पढ़ाया। अब जरा-सी असफलता मिलते ही वे टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें गिरना, फिर उठना सिखाया ही नहीं गया। उन्हें यह नहीं बताया गया कि उदासी कोई शर्म की बात नहीं। वे डरते हैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से, क्योंकि हमने उन्हें स्वीकृति की जगह प्रदर्शन

करना सिखाया। उन्हें सिखाया गया कि ‘मजबूत’ वही है, जो रोए नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि रो लेना भी कभी-कभी मजबूती की निशानी होता है।

हमें अब यह समझना होगा कि खुश रहना कोई स्वतः विकसित हो जाने वाली आदत नहीं है। अब तो यह भी सिखाने की चीज है, जैसे खाना बनाना या साइकिल चलाना। जैसे हम बच्चों को संतुलन बनाकर साइकिल चलाना सिखाते हैं, वैसे ही हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि भावनाओं का संतुलन कैसे बनाएं। उन्हें बताया होगा कि सब ठीक न हो, तब भी मुस्कुराया जा सकता है। जब मन भारी हो, तो उसे शब्द दिए जा सकते हैं। मन के अंदर उमड़ते-धुमड़ते विचारों को डायरी में लिखना, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना, या बस खुली हवा में टहलना भी मन के बोझ को हल्का कर सकता है। जब कोई कारण न भी हो, तब भी जीवन से प्रेम किया जा सकता है। हमें अपने संवादों में से सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना हटाकर

‘खुद पर ध्यान दो’ जैसी बातें जोड़नी होंगी। हमें यह मानना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य विलसिता नहीं, बल्कि जीवन जीने की बुनियादी जरूरत है। जैसे हम नियमित भोजन और व्यायाम को जरूरी मानते हैं, वैसे ही रोज कुछ समय अपने मन के लिए भी निकालना सिखाना होगा।

आज हम उन्हें सब कुछ देने को तैयार हैं- बेहतर स्कूल, बेहतरीन किताबें, महंगे ट्यूटर, विदेश में पढ़ाई के अवसर, लेकिन अगर हमने उन्हें भीतर से मजबूत नहीं किया, तो यह सब एक चमकदार आवरण से ज्यादा कुछ नहीं होगा। समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को जीवन की पढ़ाई दें- जिसमें वे खुद को समझें, स्वीकारें, और अपने ही साथ रहना सीखें।

उन्हें यह बताना होगा कि हंसी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने मन को हल्का करने के लिए होती है। उन्हें यह भी समझाना होगा कि खुशी कोई उपलब्धि नहीं, एक अभ्यास है। यह अभ्यास हर दिन, हर उम्र में किया जा सकता

है- बारिश में भीगते हुए, हवा के झोंके में आंखें मूंदते हुए या बस यों ही किसी पेड़ के नीचे बैठकर। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी सिर्फ डाक्टर, इंजीनियर, अफसर या उद्यमी न बने, बल्कि ऐसा मनुष्य बने जो जीवन को महसूस कर सके। जो यह जाने कि हार का अर्थ अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जो यह समझे कि हर दिन उत्पादक होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन जीना जरूरी है।

अगर हम बचपन से ही यह सिखा दें कि असफलता का स्वाद भी जिंदगी का हिस्सा है, तो शायद हम बच्चों के भीतर वह आत्मबल पैदा कर पाएंगे, जो उन्हें हर परिस्थिति में संभाल सके। अगर हमने उन्हें यह सिखा दिया, तो अपने वाले समय में हमारे बच्चे केवल सफल नहीं, सचमुच संतुष्ट और खुश भी होंगे। यही वह विरासत होगी, जो हम उन्हें दे सकते हैं- सबसे कीमती, सबसे स्थायी और सबसे मानवीय।

संस्कृत दिव्य ज्ञान की भाषा है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भाव भी चाहिए तभी विश्व कल्याण का रास्ता निकलेगा-सीएम योगी

वाराणसी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया को जोड़ने वाली भाषा संस्कृत ही होगी। उन्होंने कहा कि संस्कृत के उत्थान के लिए सरकार छात्रवृत्ति और उच्च स्तर पर शोध के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन सोमवार को वाराणसी के शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय में काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित सिलाई-कढ़ाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के 14वें सत्रांत के अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लगभग 250 बालक-बालिकाओं को सिलाई मशीन, लैपटॉप एवं प्रमाण पत्र भी वितरित किये।

सीएम योगी ने इस अवसर

पर कहा कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भी भारत की ही देन है। उन्होंने कहा कि



महाज्ञानी पाणिनि उसी के छात्र थे, जिनका व्याकरण हमें देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया का पहला संस्कृत महाकाव्य रचा था और आने वाले समय में दुनिया को जोड़ने वाली

भाषा संस्कृत ही होगी। उन्होंने कहा कि संस्कृत दिव्य ज्ञान की भाषा है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ

भाव भी चाहिए तभी विश्व कल्याण का रास्ता निकलेगा। उन्होंने कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए अन्नपूर्णा आश्रम के महंत शंकर पुरी को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह

मठ देव वाणी संस्कृत के लिए भी लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा मंदिर के संस्कृत महाविद्यालय के बच्चे सभी कार्यक्रमों में वैदिक मंत्रोच्चार करके माहौल को आध्यात्मिक बना देते हैं। उन्होंने कहा कि यहां गौसेवा भी बहुत अच्छी तरह की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत की यही संस्कृति रही जिस पद्धति को ये मठ बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने संस्कृत के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये हैं जिनमें छात्रवृत्ति, विद्यार्थियों के रहने-खाने की व्यवस्था और उच्च स्तर पर शोध के लिए लगातार काम शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम में सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम जुड़कर नारियों के स्वावलंबन के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रस्तुत करता है।

भरी कचहरी में पति ने पत्नी को जमकर पीटा बीच-बचाव में दो वकील घायल इस मामले में पेशी पर आए थे दोनों

लखनऊ (एजेंसी)। प्रदेश के रायबरेली से एक मारपीट का मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला जो कचहरी में पेशी पर आई थी, उसके पति ने ही उसकी पिटाई कर दी। पति ने अपनी पत्नी को भरी कचहरी में सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। इससे हंगामा मच गया। महिला को बचाने आए दो वकीलों पर भी उसने हमला कर दिया और वो दोनों भी घायल हो गए। बता दें कि अमेठी जिले के जायस कोतवाली क्षेत्र के सूबेदार का पुरवा निवासी सीमा ने बताया कि तीन साल पहले उनकी शादी कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र

‘दलितों-अल्पसंख्यकों और ओबीसी के लिए नर्क बन गया है प्रदेश’ कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर योगी सरकार

लखनऊ (एजेंसी)। प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की पिटाई से हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अजय पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं, अब योगी सरकार का आड़े होथों लेते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यूपी दलितों-अल्पसंख्यकों और ओबीसी के लिए नर्क बन गया है।

आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों के लिए नर्क बन गया है। जब कुछ हंगामा एक दलित व्यक्ति हरिओम की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर देते हैं और गर्व से दावा करते हैं कि वे ‘बाबा के

लोग’ हैं - मानो ऐसे अत्याचारों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त हो - तो वे चुप क्यों हैं?’

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल आगे लिखा कि एक बात स्पष्ट है - बाबासाहेब का संविधान इन ‘बाबा वाले लोगों’ के खिलाफ एक ढाल है, जो पिछड़ों और वंचितों

को अपमानित करने और गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। नेता ने कहा कि संविधान बचाने की हमारी लड़ाई हरिओम जैसे निर्दोष लोगों की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है।



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान ‘राहुल गांधी का नाम लेने पर बाबा के गुंडे कर रहे हत्या’

लखनऊ (एजेंसी)। प्रदेश के फतेहपुर जिले में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रायबरेली में हुए दलित युवक की हत्या के मामले पर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। अजय राय ने मृतक परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि राहुल गांधी का नाम लेने पर बाबा के गुंडे निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली में घटना के वक्त पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने बाबा के

माता-पिता से मुलाकात की और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

वहीं, मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी का नाम लेने पर बाबा के गुंडे निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली में घटना के वक्त पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने बाबा के

गुंडों के साथ मिलकर हरिओम की हत्या करवा दी। अजय राय ने मृतक परिवार को एक करड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। ‘राहुल गांधी जी का नाम लेने पर बाबा के गुंडे निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। यह सरकार गुंडे-माफिया खत्म करने की बात करती है, लेकिन उनके ही लोग खुलेआम हत्या कर रहे हैं। यूपी में आज जंगलराज चल रहा है।



‘हम तो मामा हैं यार’ कांग्रेसियों से बोले शिवराज, विरोध के बीच ठहाके मारकर हंसने लगे कांग्रेस कार्यकर्ता

सीहोर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम बिलकिसगंज में शासकीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उनका काफिला रोककर किसानों की समस्याएं उठाई और फसल बीमा व मुआवजे की मांग की। कांग्रेसियों ने नारेबाजी और गुलाब का फूल देते हुए मंत्री से संवाद की कोशिश की। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘हम तो मामा हैं यार, जहां कहते हैं रुकते हैं, बात करते हैं। पहले बात हो जाने दो फिर नारे लगाना।’ उनके इस अनापन भरे अंदाज को देखकर विरोधी नेताओं ने भी हंसी में माहौल को शांत किया। पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने बताया कि सीहोर जिले के किसानों की सोयाबीन फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन न तो मुआवजा मिला और न ही फसल बीमा का लाभ। उन्होंने अधिकारियों पर अन्य जिलों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन दिया कि फसल बीमा योजना का लाभ उन्हें मिलेगा और अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं।



पुलिस के सामने दिया बयान अस्वीकार्य, दो लोगों का आजीवन कारावास रद्द : उच्च न्यायालय

देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो लोगों के आजीवन कारावास को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि दोषसिद्धि मजिस्ट्रेट की बजाय पुलिस के समक्ष दिये गये कथित बयान पर आधारित थी, जो सबूत के रूप में अस्वीकार्य है।

उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 15 साल पहले हुए उदय प्रकाश अग्रवाल उर्फ बबलू हत्याकांड में प्रकाश पाण्डेय उर्फ विकास त्यागी और उमेश सजवाण की आजीवन कारावास की सजा रद्द कर उन्हें बरी कर दिया।

उच्च न्यायालय ने हालांकिमामले में तीन सह आरोपियों घनानंद जोशी, सूरज वर्मा और चमन लोहारी को बरी

किए जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और इस संबंध में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को यह फैसला सुनाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के खिलाफ पाण्डेय व सजवाण और मामले में तीन सह आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। अग्रवाल की 18 अप्रैल, 2010 को हत्या कर दी गयी थी और मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय ने पाण्डेय व सजवाण को तत्कालीन भारतीय दंड संहिताकी धारा 302

और शास्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई



और जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने हालांकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन

मुख्यतः पुलिस के समक्ष दिये गये कथित कबूलनामे पर आधारित थी, जो सबूत के रूप में अस्वीकार्य थी।

पीठ ने कहा कि यह बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत सह आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किये जा सकते थे। अदालत ने कहा कि यह बयान किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं किया गया था और इसलिए इसकी कानूनी वैधता नहीं थी।

अदालत ने यह भी कहा कि पांच सितंबर 2010 को रोडवेज बस स्टैंड के पास आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूसों की कथित बरामदगी की पुष्टि किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा नहीं की गयी

सीएम हिमंत सरमा बोले- ‘विनाशकारी’ है गोगोई की पाकिस्तान संबंधों पर SIT की रिपोर्ट

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनके परिवार के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट बहुत नुकसानदेह और विनाशकारी है। सरमा ने कहा कि सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस रिपोर्ट पर अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई और हम इसे बाद में पत्रकारों के सामने सार्वजनिक करेंगे। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह एक बेहद खराब रिपोर्ट है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। शर्मा ने कहा, चूंकि गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, हम चाहते हैं कि देशभर के लोग इस रिपोर्ट के बारे में जानें, इसलिए हम दिल्ली से मीडियाकर्मियों को आमंत्रित करेंगे ताकि वे उनके वास्तविक चरित्र को जान सकें। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जल्द ही

औपचारिक रूप से मंत्रिमंडल की बैठक में सूचीबद्ध की जाएगी। ‘पूरी रिपोर्ट नहीं सिर्फ सार करेंगे सार्वजनिक’ असम के सीएम ने गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु के बाद के घटनाक्रम



का हवाला देते हुए कहा, हम इसे आज ही कर सकते थे, लेकिन राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमने ऐसा न करने का फैसला किया। सरकार पूरी रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसका सार सार्वजनिक करेगी। इस रिपोर्ट

में कई सरकारी राज और कई लोगों के बयान दर्ज हैं। इसलिए हम रिपोर्ट का सार और उससे जुड़े दस्तावेज प्रकाशित करेंगे ताकि लोग इस बारे में जान सकें। बता दें कि विशेष पुलिस

से जांच करेगी और इसे सार्वजनिक करने से पहले मंत्रिमंडल के समक्ष चर्चा के लिए रखेगी। असम के सीएम ने किया था ये दावा

सरमा ने पहले दावा किया था कि एसआईटी ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख की नापाक गतिविधियों में एक ब्रिटिश नागरिक जिसने एक भारतीय सांसद से शादी की है की संलिप्तता स्थापित की है। उन्होंने दावा किया था कि जांच से यह भी पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्रालय ने असम के एक सांसद की अपने देश में यात्रा को सुगम बनाया। गोगोई ने पूर्व में दावा किया था कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोप बॉलीवुड की किसी सी-ग्रेड फिल्म की तरह हैं, जो फलॉप हो जाएंगी क्योंकि असम के लोग सब कुछ समझते हैं।

सीट बंटवारे पर लालू-तेजस्वी से बात करेंगे कांग्रेस के तीन पर्यवेक्षक, इस बैठक में तय होगी चुनावी रणनीति

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा की चुनाव की रणभेरी बज गई है। लेकिन अभी तक भाजपा-जेडीयू और कांग्रेस-राजद गठबंधन में अभी तक सीट के बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने तीनों वरिष्ठ पर्यवेक्षक (अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी) को बिहार पहुंचने के लिए कहा है। ये तीनों नेता सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रत्याशी को नैतिगत निर्देश देंगे, सभी की बात सुनेंगे, नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेंगे।

पार्टी के तीनों वरिष्ठ पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान हर जिले में होने वाले स्टार प्रचारक की रैली का सुचारु आयोजन सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के नाराज नेताओं को मनाएंगे और राजद प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव से सीटों के बंटवारे पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस

सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों दो से तीन दिन में पार्टी यह तय करेगी कि कौन सा पर्यवेक्षक कौन सा जिला दिया जाएगा। इन सभी पर्यवेक्षकों की एक संयुक्त बैठक

अपनी छाप है। सीमांचल का इलाका बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। यहां की 25-30 सीटों पर इनका प्रभाव हो सकता है। इसलिए आलाकमान ने इन्हें चुना है।



इसलिए कांग्रेस ने तय किए हैं पर्यवेक्षक हाल ही में कांग्रेस ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के अलावा जमीनी स्तर पर चुनावी तंत्र को मजबूत करने के लिए 41अन्य नेताओं को जिला चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है। इन जिला पर्यवेक्षकों का मुख्य कार्य

जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखना और संबंधित जिलों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में सहयोग करना होगा। यह कदम कांग्रेस की चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन जिला आब्जर्वरों में अविनाश पांडेय, कामेश्वर पटेल, हरिश् चौधरी, काजी निजामुद्दीन, अजय कुमार लल्लू, भक्त चरण दास, अजय राय, शुभंकर सरकार, सतेज बंडी पाटिल, इशा खान चौधरी, तनुज पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल चौधरी, अभिषेक दत्त, रामकृष्ण ओझा शामिल हैं। वहीं, सत्यनारायण पटेल, चेतन चौहान, वैबी श्रीनिवास, विक्रंत भूरिया, पीएस रेड्डी, राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पंडेय सिंह, राणा गुरजीत, अशोक चंदना, शिखरीत कदम, रामलाल जाट, इशा खान चौधरी, रफीक खान शामिल हैं। दिनेश गुर्जर, अभिमन्यु पुनिया, हिना कावरे, वैरेन्द्र राठोड़, संजय कपूर, रोहित चौधरी, अमित सिहाग, विपिन वानखेड़े, नीरज दीक्षित, प्रवीण पाठक, करण सिंह उचियाड़ और अनिल चोपड़ा भी शामिल हैं।

अवैध निर्माण पर पालिका का हथौड़ा नवी बस्ती में टूटा मकान- मचा हड़कंप

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका क्षेत्र के नवी बस्ती इलाके में एक बार फिर अवैध निर्माण पर पालिका प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। नवी बस्ती स्थित घर नंबर 259, मनपा आरोग्य केंद्र के सामने मनोबा नाडर द्वारा अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत प्रभाग समिति क्रमांक दो के सहायक आयुक्त माणिक जाधव को मिली थी।

पालिका आयुक्त अनमोल सागर, अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके और उपायुक्त बिग्नम दराडे वेड निर्देशानुसार, सहायक आयुक्त माणिक जाधव, बीट निरीक्षक आकाश भोर्डे और धनराज पाटील के नेतृत्व में अतिक्रमण दल ने मौके पर पहुंचकर उक्त अवैध निर्माण को पुलिस बंदोबस्त में ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान भिवंडी शहर पुलिस थाने की टीम भी मौजूद थी।

जानकारी के अनुसार, महानगर पालिका प्रशासन ने 2022 से अब तक शहर में कुल 291 अवैध मकानों



के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया है। पालिका के अनुसार, अवैध निर्माण रोकने और निर्माणाधीन इमारतों को ध्वस्तीकरण की यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। आज कगी कार्रवाई वेड बाद अवैध धनराज पाटील के नेतृत्व में अतिक्रमण दल ने मौके पर पहुंचकर उक्त अवैध निर्माण को पुलिस बंदोबस्त में ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान भिवंडी शहर पुलिस थाने की टीम भी मौजूद थी।

पालिका के अधिकारियों ने साफ किया कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के अनुसार सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पालिका प्रशासन की यह कड़ी कार्रवाई शहर में 'अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेस'

नीति को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर रोक लागेगी और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित होगा।

केमिकल गोदाम में भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर खाक

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी के सावदे गांव इलाके में रविवार रात एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से अपरातफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने देखते ही देखते पास के एक अन्य बड़े गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि दोनों गोदामों में कपड़ा, कागज, केमिकल और अन्य जलनशील सामान रखा हुआ था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। घटना रविवार रात करीब 9 बजकर 45 मिनट पर हुई। चममदीवों के मुताबिक, कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और लपटें आसमान तक उठने लगीं। सूचना मिलते ही भिवंडी महानगरपालिका के अग्निशमन दल की दो गाड़ियाँ और एक ट्रैक्टर मौके पर पहुंचा। आग पर काबू पाने के लिए कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर महानगरपालिकाओं की फायर ब्रिगेड की टीम भी बुलाई गई। फायर ब्रिगेड के जवानों



से आग तेजी से फैल गई। सोभाग्य से रविवार का दिन होने के कारण गोदाम बंद था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। अधिकारियों का कहना है कि आग को पूरी तरह नियंत्रण में लाने में करीब चार से पांच घंटे का समय लगा। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

उर्दू साहित्य कला अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह का तीन दिवसीय उद्घाटन-मंत्री माणिकराव कोकाटे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

उर्दू घर मराठी और उर्दू साहित्य के आदान-प्रदान का एक सांस्कृतिक केंद्र है। सरकार इस उर्दू घर को नवीनीकरण के लिए प्रयास करेगी। अल्पसंख्यक विकास एवं औकाफ मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने कहा कि वह उर्दू स्कूलों और छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के प्रति भी सकारात्मक हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उर्दू साहित्य अकादमी की एक नई समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा।

हाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर वहीं डोम में आयोजित तीन दिवसीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन अल्पसंख्यक विकास एवं औकाफ मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने किया। इस अवसर पर 'उर्दू की दुनिया' प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। वे इस

अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर पूर्व अल्पसंख्यक विकास एवं औकाफ मंत्री नवाब मलिक, पूर्व मंत्री अनीस अहमद, विधायक सना मलिक, पूर्व विधायक जोशान सिद्दीकी, पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मार्क सिंह, गीतकार, औकाफ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी, पटकथा लेखक जावेद अख्तर, विभागीय सचिव रुचेरा जयवंशी, आयुक्त प्रतिभा इंगले सहित अधिकारी और लेखक उपस्थित थे। इस अवसर पर दो पुस्तिकाओं, उर्दू सीखे और मराठी शिकुइया का अनावरण किया गया।

अल्पसंख्यक विकास मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने कहा कि शिवाजी महाराज, महामा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज और संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जैसे महापुरुषों ने समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हुए समावेशिता, शिक्षा, भाषा विकास और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मूल्यों की परंपरा का निर्माण किया। उनके विचारों

के प्रभाव से ही उर्दू सहित सभी भाषाओं को महाराष्ट्र में सम्मान का स्थान प्राप्त हुआ। इन्होंने आदर्शों की प्रेरणा से आज उर्दू भाषा के स्तर्णिम सफर का जश्न मनाया जा रहा है। उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि संस्कृति की खुशबू, विचारों का पुल और आत्मा की आवाज़ है। एडवोकेट कोकाटे ने अकादमी के कार्यों के बारे में बताया कि 450 से ज्यादा साहित्यिक कार्यक्रम, 250 से ज्यादा कवि सम्मेलन, 150 से ज्यादा कार्यशालाएँ और 100 से ज्यादा पुस्तक प्रकाशनों ने उर्दू साहित्य की परंपरा को समृद्ध किया है। अकादमी ने 25 से ज्यादा जिलों में कार्यक्रम चलाए हैं और ग्रामीण इलाकों में उर्दू फुले, राजर्षि शाहू महाराज और प्रेमियों तक पहुँच बनाई है। उर्दू एक भारतीय भाषा है और लगभग सात करोड़ लोग इसे अपनी पहली भाषा के रूप में और 10 करोड़ लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र में सात प्रतिशत लोग उर्दू बोलते हैं और 25 से ज्यादा उर्दू

दैनिक समाचार पत्र संचालित हो रहे हैं। उर्दू घर योजना के तहत नांदेड, मालेगांव, जलगांव, सोलापुर और नागपुर में निर्माण कार्य चल रहा है। नए लेखकों, उर्दू शिक्षकों, लेखकों और कवियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के 1800 उर्दू स्कूलों में नौ लाख छात्रों को उर्दू पढ़ाई जाती है। 'उर्दू लर्निंग ऐप' के माध्यम से प्रतिवर्ष 50 हजार विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। 3 वर्षों में 100 जिला स्तरीय साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किए गए।

अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं शैक्षिक प्रोत्साहन जैसे अनेक योजनाएँ अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार उर्दू साहित्य अकादमी सहित अल्पसंख्यक विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त विकास निधि उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेगी।

शिंदे गुट ने संजय राउत को दिया बड़ा 'ऑफर', कहा- 'कागज लेकर आइए और...'

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं के साथ आने की अटकलों के बीच एखनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के शिवसैनिकों का साथ छूट गया। अब उद्धव, मनसे की बैसाखी का सहारा लेकर चलना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी खड़ी नहीं कर सकते. राज ठाकरे को साथ लेने पर भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला है।

वहीं, बिहार में एसआईआर को लेकर भी संजय निरुपम का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, 'बिहार में 40 लाख फर्जी वोटर थे, जिनका नाम हटाया गया. महाराष्ट्र के भी फर्जी वोटर हटाने के लिए SIR प्रक्रिया होनी चाहिए. फर्जी, बांग्लादेशी वोटर हटाने चाहिए. UBT के उम्मीदवार ऐसे ही फर्जी मतदाताओं के नाम पर चुनकर आए.'



उससे कहा कागज पत्र लेकर आओ और आधी संपत्ति लेकर जाओ.' संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे को भी यही कहना चाहते हैं. कागज लेकर आइए और आधी संपत्ति लेकर जाइए. जैसी हालत विधानसभा चुनाव में हुई, वैसी ही हालत स्थानीय निकाय में भी होगी।

इस सवाल के जवाब में संजय निरुपम ने कहा, 'संविधान के अनुसार एकनाथ

शिंदे डिटी सीएम हैं. जब संविधान पर भरोसा नहीं है तो 'संविधान बचाओ' रैली क्यों निकालते हैं?' संजय निरुपम ने आगे कहा, 'उद्धव ठाकरे बालासाहेब ठाकरे के रक्त के वारिस हो सकते हैं पर विचारों के वारिस नहीं हैं. एकनाथ शिंदे सहित शिवसैनिक बालासाहेब ठाकरे के शिष्य हैं।

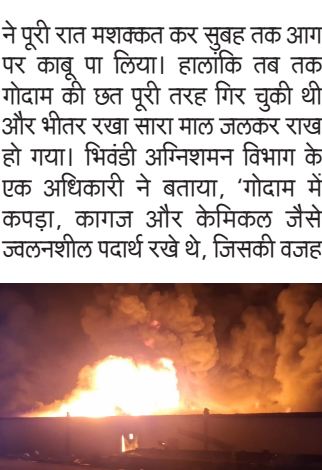
संजय निरुपम ने कहा, 'पिछले चार साल से रोने वाले उद्धव ठाकरे ने पुणे में जाकर एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया कि उन्होंने पक्ष और बाप चुरा लिया. उद्धव ठाकरे का ये कुविचार है. पार्टी चुराई नहीं, पार्टी बचाई गई है. बालासाहेब ठाकरे के विचार को बचाया गया है।

संजय निरुपम ने आगे शरद पवार NCP साथ अनैतिक गठबंधन किया. विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे 109 सीट पर लड़े और 20 विधायक जीते. एकनाथ शिंदे ने 80 सीट पर उम्मीदवार खड़ा किया जिसमें से 60 विधायक जीतकर आए. जनदेश का सीधा जवाब है कि एकनाथ शिंदे ने सही निर्णय लिया था।

भिवंडी में कचरा माफिया बेलगाम, खुले ट्रकों से उड़ रहा जहर, प्रशासन मौन

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज



भिवंडी-निजामपुर शहर महानगर पालिका क्षेत्र में कचरा ढुलाई व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है। नगर पालिका द्वारा नियुक्त निजी ठेकेदार खुले ट्रकों, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों और बिना लाइसेंस ड्राइवरों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 400 मेट्रिक टन कचरा शहर से बाहर ले जा रहे हैं। इस गंभीर अनियमितता के बावजूद नगर पालिका प्रशासन और यातायात पुलिस विभाग चुपची साधे हुए हैं। खुले ट्रकों में ढोए जा रहे कचरे से उड़ने वाली धूल और दुर्गंध ने नागरिकों का जीना दूधर कर दिया है। सड़कों पर निकलना अब लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। नागरिकों का कहना है कि इस तरह की कचरा ढुलाई न केवल शहर की स्वच्छता के लिए घातक है बल्कि बीमारियों के फैलने का भी प्रमुख कारण बनती जा रही है। नगर पालिका के आरोप एवं स्वच्छता विभाग प्रमुख से लेकर उपायुक्त और आयुक्त तक को



इस स्थिति की पूरी जानकारी है। इसके बावजूद ठेकेदारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में स्वच्छता विभाग से संपर्क किया तो संबंधित अधिकारी ने अस्पष्ट जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। गौरतलब हो कि भिवंडी शहर को पांच

प्रभाग समितियों में विभाजित किया गया है, जहां अलग-अलग कंपनियों को कचरा संकलन और ढुलाई का ठेका दिया गया है.प्रभाग समिति क्रमांक 1 का ठेका मुंबई की नितीन बनसोड कंपनी को मिला है, जो 25 घंटा गाड़ियों और 7 ट्रकों के माध्यम से चाविड्र इर्पिंग

ग्राउंड तक कचरा पहुंचाती है।प्रभाग समिति क्रमांक 2 का ठेका भिवंडी की डिपल इंटरप्राइजेस कंपनी को दिया गया है, जो 22 घंटा गाड़ियों और 8 ट्रकों से कचरा ढोती है। प्रभाग समिति क्रमांक 3 का कार्य नवी मुंबई की प्रियंका थोरबे कंपनी कर रही है, जो 23 घंटा गाड़ियों और 8 ट्रकों का उपयोग करती है।प्रभाग समिति क्रमांक 4 का ठेका भिवंडी की बुबूरे एसोसिएशन कंपनी को मिला है, जो 20 घंटा गाड़ियों और 6 ट्रकों के माध्यम से कचरा संकलन करती है। प्रभाग समिति क्रमांक 5 में उल्लासनगर की कोर्णाक कंपनी 20 घंटा गाड़ियों और 5 ट्रकों से कचरा ढुलाई करती है। इन कंपनियों ने म्हाडा कॉलोनी, बहत्तर गाला, फेना पाडा, सुभाष नगर और एलेक्सी टॉकीज के पास कचरा संकलन केंद्र बनाए हैं। प्रत्येक प्रभाग में दो जेसीबी मशीनें और कुल ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं कर सकी है। अंधोरे का कहना है कि क्या ठेकेदारों के प्रभाव के आगे प्रशासन की कार्यप्रणाली यूं ही बेबस बनी रहेगी और शहर की स्वच्छता व्यवस्था इसी तरह दम तोड़ती रहेगी.।

और न ही यातायात विभाग इन पर कोई सख्त कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर अंधोरे ने बताया कि खुले ट्रकों से उड़ती धूल और कचरे से उठती बदबू से क्षेत्र में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर कचरे के ढेर खुले में पड़े रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। जब नगर पालिका को इस अव्यवस्था की पूरी जानकारी है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इसके पूर्व कचरा उठाने वाले आर.एन.बी. कंपनी के ठेकेदार को पालिका प्रशासन मेहरबानी करते हुए अपनी करोड़ों कीमत की आर.सी.एम वाहन सहित अन्य वाहनों को मात्र एक रुपये भाड़े पर दे दिया था। किन्तु वहीं ठेकेदार उन वाहनों को अब जब कर लिया है। पालिका प्रशासन इस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं कर सकी है। अंधोरे का कहना है कि क्या ठेकेदारों के प्रभाव के आगे प्रशासन की कार्यप्रणाली यूं ही बेबस बनी रहेगी और शहर की स्वच्छता व्यवस्था इसी तरह दम तोड़ती रहेगी.।

मुंबई के वार्ड सीमांकन की अधिसूचना जारी, 227 सीटों पर चुने जाएंगे पार्षद

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आगामी बृह-मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों को लेकर अब चुनावी तैयारियों औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं. महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें शहर के चुनावी वार्डों का अंतिम गठन तय किया गया है. इस अधिसूचना में मुंबई को कुल 227 चुनावी वार्डों में बांटा गया है, और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा. सरकार ने यह अधिसूचना मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5 और 19 के तहत जारी की है. इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग की मंजूरी भी प्राप्त है. अधिसूचना 22 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मसौदा वार्ड संरचना पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के बाद जारी की गई.



ज्यादा मेहनत करनी होगी. वार्ड सीमांकन पुरा होते ही शहर के राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है. अब हर पार्टी गहराई से अध्ययन कर रही है कि किस वार्ड में उसके लिए

अवसर ज्यादा हैं और कहाँ पर चुनौती कठिन होगी. इस समय से ही उम्मीदवारों का चयन शुरू हो जाएगा और चुनाव प्रचार की योजना बनाई जाएगी. इस बदलाव का असर आम लोगों पर भी पड़ेगा. अब हर वार्ड में पार्षद का प्रतिनिधित्व तय होगा और स्थानीय मुद्दों की आवाज सीधे उनके प्रतिनिधि तक पहुंचेगी. इससे लोगों की स्थानीय समस्याओं का समाधान आसान हो सकेगा. अब जब वार्ड सीमांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो मुंबई का राजनीतिक दल अपने सबसे बड़े नामांकित चुनाव की तैयारी में पूरी तरह लग जाएगा. राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवार अब सक्रिय रूप से चुनावी रणनीति बनाने में जुटेगे, आने वाले महीनों में चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी.

मध्यप्रदेश में 'फर्जी' शराब चालान घोटाले में ईडी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया

भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने मध्यप्रदेश में कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये के फर्जी शराब चालान घोटाले के सिलसिले में धनशोधन रोधी कानून के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को तीन अक्टूबर को इंदौर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएएल) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। इसने कहा कि एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें आठ अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी के अनुसार, दोनों की पहचान "मुख्य षड्यंत्रकारियों" के रूप में की गई है, जिन्होंने "धोखाधड़ीपूर्ण" तरीका तैयार किया और उसे क्रियान्वित किया, जिससे शराब ठेकेदारों को "अवैध" रूप से लाभ प्राप्त करने में मदद मिली, जबकि



जिसमें आरोपी शराब ठेकेदारों ने शुरू में नाममात्र राशि के ट्रेजरी चालान जमा किए, लेकिन जानबूझकर "शब्दों में रुपये" खंड को खाली छोड़ दिया। इसने कहा कि राशि जमा करने के बाद उन्होंने धोखाधड़ी से अंकों और शब्दों में बढ़ा-चढ़ाकर राशि भर दी।

ईडी ने कहा, "इन छेड़छाड़ की गई चालान प्रतियों को बाद में देशी शराब के गोदामों या जिला आबकारी कार्यालयों (विदेशी शराब के मामले में) में आबकारी शुल्क, मूल लाइसेंस शुल्क या न्यूनतम गारंटी प्रतिबद्धताओं के भुगतान के झूठे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया।" इसने कहा कि इन जाली दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों ने "अवैध" एनओसी और शराब लाइसेंस अनुमोदन प्राप्त किए, जिससे मध्यप्रदेश सरकार के साथ "धोखाधड़ी" हुई।

धनशोधन की जांच इंदौर (रावजी थाना) पुलिस द्वारा कुछ शराब ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से शुरू हुई है, जिसमें कथित तौर पर ट्रेजरी चालान में हेराफेरी और जालसाजी के जरिए सरकारी खजाने को 49.42 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

पुणे में अजीबोगरीब मामला, ब्रांडेड जूते-चप्पलों का शौक पूरा करने मां-बेटीं बनीं फर्जी IPS, ऐसे हुई गिरफ्तार

पुणे के एमजी रोड पर स्थित एक प्रतिष्ठित ब्रांडेड चप्पलों की दुकान में अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां एक मां-बेटी की जोड़ी खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर दुकान से मुफ्त में महंगी चप्पलें ले उड़ी. बाद में मामला खुला तो पता चला कि दोनों फर्जी पुलिस काई दिखाकर दुकानदार को धमका रही थीं.

13 सितंबर की शाम को मिनाज मुर्तजा शेख (उम्र 40) और उनकी बेटी रिबा मुर्तजा शेख (उम्र 19) पुणे के एमजी रोड पर एक जानी-मानी ब्रांडेड चप्पल की दुकान में पहुंचीं. मिनाज ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताते हुए नकली पहचान पत्र दिखाया. उन्होंने दुकानदार से कहा, 'घर में शादी है, जल्दी में फोन और पर्स घर पर ही



मां-बेटी के आत्मविश्वास और काई देखकर वह मान गया. दोनों ने लगभग 17 हजार रुपये की महंगी चप्पलें और जूते चुने और यह कहकर निकल गईं

कि भुगतान हम कमिश्नर ऑफिस से करवा देंगे. कुछ ही देर बाद दुकानदार को एहसास हुआ कि शायद उसे ठगा गया है.दुकानदार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. एमजी रोड पुलिस ने आसपास के पन्ऊऊ फुटेज खंगाले, जिसमें मां-बेटी को दुकान से जाते हुए

देखा गया. फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों की पहचान की और जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 1 और 2 अक्टूबर को मिनाज और रिबा को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से करीब 45 हजार रुपये कीमत का चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने पहले भी इसी तरह के कई दुकानों से सामान लेने की कोशिश की थी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मां-बेटी ने बहुत चालाकी से पूरी कहानी रची थी. नकली पुलिस काई भी असली की तरह लग रहा था. उनके आत्मविश्वास और व्यवहार को देखकर कोई भी धोखा खा सकता था.

आदिवासी नेता खगेन मुर्मू पर हमला : संबित पात्रा ने ममता पर फोड़ा ठीकरा, बोले- टीएमसी ने शुरू किया जंगल राज

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में आदिवासी नेता और दो बार सांसद रहे खगेन मुर्मू पर हुए हमले को लेकर ममता सरकार की आलोचना की और इसे पश्चिम बंगाल में जंगल राज का उदाहरण बताया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बाद राहत के लिए मुर्मू और स्थानीय विधायक शंकर घोष के दौरे के दौरान उन पर हमला करने के लिए उकसाया, जिससे मुर्मू के सिर में चोट आई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी द्वारा शुरू किया गया 'जंगल राज' देखा है। जब खगेन मुर्मू बाद राहत के लिए जलपाईगुड़ी के नागराकाटा जा रहे थे, तो स्थानीय विधायक शंकर घोष भी उनके साथ थे। उस समय,

टीएमसी नेताओं के इशारे पर, पार्टी कार्यकर्ताओं ने खगेन मुर्मू और शंकर घोष पर हमला किया। पूरे भारत ने इसे देखा। खगेन मुर्मू को सिर में चोटें आई हैं... आज, एक आदिवासी नेता और 2 बार के सांसद पर अमानवीय



हमारे विधायक और सांसद (शंकर घोष और खगेन मुर्मू) पर हमला करवाया।'

भाजपा विधायक शंकर घोष ने आरोप लगाया कि राज्य में बाद और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए राहत

सामग्री वितरित करते समय उत्तर बंगाल के नागराकाटा में उन पर और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने कथित हमले को लेकर बनर्जी की आलोचना की और इसे 'टीएमसी का जंगल राज' बताया।

कथित हमले का वीडियो शेयर करते हुए, अमित मालवीय ने एक्स पर

'उत्तर बंगाल में बाद और भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। इसके बावजूद, मेरा मानना ​​है कि ममता बनर्जी टॉलीवुड संगीत की धुनों पर नाच रही थीं। उन्हें पता है कि इससे लोगों में गलत संदेश गया है। इसलिए, उन्होंने

हमारे विधायक और सांसद

घोष ने आरोप लगाया कि राज्य में बाद और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए राहत

सामग्री वितरित करते समय उत्तर बंगाल के नागराकाटा में उन पर और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने कथित हमले को लेकर बनर्जी की आलोचना की और इसे 'टीएमसी का जंगल राज' बताया।

कथित हमले का वीडियो शेयर करते हुए, अमित मालवीय ने एक्स पर

लिखा, 'बंगाल में टीएमसी का जंगल राज! भाजपा सांसद खगेन मुर्मू, जो एक सम्मानित आदिवासी नेता और उत्तरी मालदा से दो बार सांसद रहे हैं, पर टीएमसी के गुंडों ने उस समय हमला किया जब वे जलपाईगुड़ी के दुआई क्षेत्र के नागराकाटा में विनाशकारी बारिश, बाद और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद करने जा रहे थे।'

एक्स पोस्ट में लिखा है कि भाजपा नेता ने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर राहत कार्य करने के लिए हमला किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री बनर्जी और सत्तारूढ़ टीएमसी 'कार्रवाई से गायब' हैं। जब ममता बनर्जी अपने कोलकाता कार्निवल में नाच रही हैं, तब टीएमसी और राज्य प्रशासन कार्रवाई से गायब है। जो लोग वास्तव में लोगों की मदद कर रहे हैं, भाजपा नेता और कार्यकर्ता, उन पर राहत कार्य करने के लिए हमला किया जा रहा है। यह टीएमसी का बंगाल है, जहाँ क्रूरता का बोलबाला है और दया को सज़ा दी जाती है।

भारत का नया सीक्रेट वेपन, अब समुद्र में नहीं छिप पाएंगा दुश्मन

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने सोमवार को विशालापतनम स्थित नौसेना गोदी में आयोजित एक समारोह में अपने दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत, INS एंड्रोथ को नौसेना में शामिल किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों और शिपयार्ड प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेढारकर ने की। कोलकाता स्थित एक जहाज निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित, एंड्रोथ पोत विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा के लिए तेजी से महत्वपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। नौसेना के अनुसार, एंड्रोथ के शामिल होने से उसकी समग्र पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएँ बढ़ेंगी, विशेष रूप से तटीय और उथले पानी में संचालन के लिए, जो भारत की अपनी घरेलू रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है।

ईएनसी की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति

में कहा गया है कि एंड्रोथ का जलावतरण नौसेना के स्वदेशीकरण और क्षमता संवर्धन की दिशा में चल रहे प्रयासों में

घटकों को भारत में ही प्राप्त करके किया गया है, जो देश की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता को दर्शाता है। एंड्रोथ



एक और बड़ा कदम है। यह विकास स्थानीय स्तर पर प्राप्त तकनीक और विशेषज्ञता के माध्यम से रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की व्यापक राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप है। इस पोत का निर्माण 80 प्रतिशत से अधिक

को समुद्री इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती दक्षता का प्रमाण माना जाता है। नौसेना ने इस बात पर जोर दिया कि यह दृष्टिकोण परिचालन आवश्यकताओं और घरेलू उद्योग विकास, दोनों का समर्थन करता है।

आईपीएस असरा गर्ग के नेतृत्व में एसआईटी ने करूर भगदड़ की शुरु की जांच घटनास्थल का किया निरीक्षण

चेन्नई। विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग ने रविवार को तमिलनाडु के करूर जिले में जांच शुरू की, जहां अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलनाा वैकी कड़गम की रैली में भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी का गठन 3 अक्टूबर को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया था, जब उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर की भगदड़ को एक बड़ी मानव निर्मित आपदा बताया था। एसआईटी के अधिकारियों ने वेलुसामीपुरम स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जहां पार्टी की राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी। यह समिति उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित की गई है। हमने आज जांच शुरू कर दी है।

तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक गर्ग ने करूर में संवाददाताओं



को बताया। चूँकि आज इस मामले में हमारा पहला दिन है, इसलिए हम अभी विवरण साझा नहीं कर सकते। गर्ग एक एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें दो पुलिस अधीक्षक (एस विमला और सी श्यामला देवी), एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दो पुलिस उपाधीक्षक और पांच निरीक्षक शामिल हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि हमने जिला पुलिस अधिकारियों और मौके पर मौजूद वर्दीधारी कर्मियों से पूछताछ की है कि भीड़भाड़ क्यों हुई और कैसे भगदड़

मची। अधिकारी ने बताया कि 4 अक्टूबर तक करूर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एन प्रेमनाथ जॉच का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने अदालत के आदेश के बाद मामले के दस्तावेज़ एसआईटी को सौंप दिए। करूर पुलिस ने अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार टीवीके सदस्यों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सत्तारूढ़ डीएमके सरकार द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन द्वारा भगदड़ के एक दिन बाद जांच शुरू करने के बाद हुई है।

लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रहे 'झूठे और

सुनियोजित अभियान' पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वांगचुक पर पाकिस्तान और चीन से संबंध होने के आरोप निराधार हैं और इन्हें केवल उनके गांधीवादी आंदोलन को बदनाम करने के लिए फैलाया जा रहा है। गीतांजलि ने याचिका में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत वांगचुक की हिरासत के बाद उनके खिलाफ गलत प्रचार किया गया।

इसमें कहा जा रहा है कि उनके पाकिस्तान और चीन से संबंध हैं, जो पूरी तरह गलत हैं। उनका यह आंदोलन लद्दाख की संवेदनशील परिस्थितिकी,

ग्लेशियरों और स्थानीय लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है।



याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह का प्रचार खतरनाक है और लोकतांत्रिक असहमति को कलंकित करता है। यह पर्यावरणीय आंदोलनों

को 'राष्ट्रविरोधी' दिखाने का प्रयास है। गीतांजलि ने अदालत से अपील की कि वांगचुक की गिरफ्तारी उनके मौलिक

पर जोर दिया और बताया कि उन्होंने हमेशा अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख की परेशानियों, पिछले ग्लेशियर और स्थानीय लोगों की संवैधानिक मांगों विशेष रूप से छठी अनुसूची के तहत संरक्षण और स्वायत्तता के लिए आवाज़ उठाई है।

बता दें कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में बड़े प्रदर्शनों के बाद रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन प्रदर्शनों में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान चार लोगों की मौत हुई और लगभग 90 लोग घायल हुए। वांगचुक वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद देशभर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी समूहों ने विंता जताई है और इसे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाने की कोशिश बताया है।

पाकिस्तान में पुलिस चौकी पर आतंकियों का हमला, एक जवान की मौत

पशावर। उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोमवार को एक पुलिस चौकी पर आतंकवादियों के हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और अर्धसैनिक बल का एक जवान घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, कोहाट जिले के दर्रा आदम खेल में टोर चप्पूर पुलिस चौकी पर रात करीब एक बजे अज्ञात हमलावरों ने कई तरफ से गोलीबारी की। कोहाट के जिला पुलिस अधिकारी ने जाहिदुल्ला खान ने बताया कि पुलिस और हमलावरों के बीच ढाई घंटे तक चली गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि

एक जवान घायल हो गया।

जाहिदुल्ला ने बताया कि हमलावरों का लक्ष्य चौकी पर कब्जा करना था लेकिन उनका प्रयास विफल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तीन विस्फोटक उपकरण जबा कर लिए हैं तथा तलाशी अभियान जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस हमले की हमले की निंदा की घायल अर्धसैनिक बल के जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में एक सैनिक के मारे जाने और एक अन्य के घायल होने के एक दिन बाद हुआ।



माउंट एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान का कहर जिंदगी और मौत के बीच फंसे 1000 पर्वतारोही

बीजिंग। माउंट एवरेस्ट के तिब्बती ढलानों पर बर्फीले तूफान के बाद 1000 से अधिक पर्वतारोही फंस गए हैं, जबकि 350 अन्य को ग्रामीणों और बचाव दलों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। रविवार को शिविर स्थलों पर फंसे पर्वतारोहियों की स्थिति हिमपात होने के कारण और भी खराब हो गई। सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण और बचावकर्मी आवश्यक सामान लेकर घटनास्थल की ओर पहुंचे, जहां

शुक्रवार से लगातार हिमपात हो रहा है। 'बीबीसी' ने सोमवार को सरकारी चैनल सीसीटीवी के हवाले से बताया कि 200 से अधिक पर्वतारोही अब भी बर्फीले तूफान में फंसे हुए हैं। लगभग 350 पर्वतारोहियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पहले की खबरों में कहा गया था कि चीन की ओर स्थित कर्मा घाटी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ढलानों पर 1, 000 से अधिक



पर्यटक पर्वतारोही फंसे हुए हैं।

फंसे पर्वतारोहियों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से पता चलता है कि रविवार को दूरस्थ क्षेत्र में बाढ़ों की गरज के बीच, तेज हवाओं और लगातार बर्फबारी के कारण रास्ते पूरी तरह से बर्फ में दब गए। चीन में माउंट एवरेस्ट को माउंट क्योमोलंग्मा कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8, 849 मीटर से अधिक है और यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस बीच, दक्षिण चीन के ग्वांगदोंग प्रांत के झानजियांग शहर के श्वेन काउंटी के पूर्वी तट पर रविवार को तूफान मैथेमो ने दस्तक दी। स्थानीय सरकारों ने ग्वांगदोंग और हैनान के दक्षिणी प्रांतों से लगभग 3, 47, 000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

बांग्लादेश में सेना हुई मुस्तैद, 17 जंगी जहाज व गश्ती हेलिकॉप्टर किए तैनात

ढाका। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंध कुछ तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने समुद्री क्षेत्र में 17 युद्धपोत और गश्ती हेलिकॉप्टर तैनात किए हैं। हालांकि, यह कोई सैन्य लड़ाई नहीं, बल्कि हिल्सा मछली की सुरक्षा के लिए किया गया कदम है।

हिल्सा मछली हेरिंग जैसी दिखती है और इसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मछलियों में गिना जाता है। भारत में भी यह खास पसंदीदा मछली है। बांग्लादेश में हिल्सा की सुरक्षा और प्रजनन क्षेत्रों की रक्षा के लिए सेना को



तैनात किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने 4 से 25 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। इस दौरान मछुआरों को मुआवजे के रूप में चावल दिया जा रहा है, ताकि वे प्रजनन क्षेत्रों में मछली न पकड़ें। 17 युद्धपोत और गश्ती हेलिकॉप्टर समुद्र में विदेशी मछुआरों की घुसपैठ रोकने और हिल्सा प्रजनन क्षेत्र की निगरानी करेंगे। इससे बांग्लादेश की मछली उत्पादन और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह कदम बांग्लादेश की आर्थिक और जैविक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत समेत पड़ोसी देशों में भी इस दिशा में चर्चा हो रही है।

Facebook: <https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044>

Twitter: <https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqaq2tVMw&s=08>

Mobile No: 7007837917